04 - सदन में बहस का अभिप्राय

05 - स्वराज व स्वधर्म के प्रति स्वाभिमान के जागरणकर्ता

06 - अब तक सिर्फ 60 प्रतिशत कचरा हटा पाई कंपनी, निर्धारित समय...

07 - प्रशिक्षणार्थी उप जिलाध्यक्षों ने विधानसभा का भ्रमण...

सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 323, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

भारत में मिडिल क्लास के सपनों पर मंडरा रहा है ये खतरा

निखिल इनामदार

भारत की सॉफ़्टवेयर इंडस्ट्री बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रही है। देश में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) ने मिड और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर 12 हज़ार से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान किया है। इससे कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में दो फ़ीसदी की कमी आएगी। यह कंपनी लगभग पांच लाख से ज़्यादा आईटी प्रोफ़ेशनल्स को रोज़गार देती है और 283 अरब डॉलर की भारतीय सॉफ़्टवेयर इंडस्ट्री का अहम हिस्सा मानी जाती है।

यह देश में व्हाइट-कॉलर नौकरियों की रीढ़ कही जाती है। व्हाइट कॉलर नौकरियां ऐसी नौकरियां होती हैं, जिनमें दफ़्तर या पेशेवर माहौल में काम किया जाता है। इनमें शारीरिक मेहनत कम और दिमाग़ी या मैनेजमेंट से जुड़ा काम ज़्यादा होता है। टीसीएस का कहना है कि यह क़दम कंपनी को 'भविष्य के लिए तैयार' करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि वह नए क्षेत्रों में निवेश कर रही है और बड़े पैमाने पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अपना रही है।

पिछले कई दशकों से टीसीएस जैसी कंपनियां कम लागत पर वैश्विक ग्राहकों के लिए सॉफ़्टवेयर बनाती रही हैं, लेकिन अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के चलते कई काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं और ग्राहक नई तकनीक पर आधारित समाधानों की मांग कर रहे हैं।

कंपनी ने कहा, 'कई री-स्किलिंग और नई भूमिकाओं में नियुक्ति की पहल चल रही है। जिन सहयोगियों की नियुक्ति संभव नहीं है, उन्हें कंपनी से रिलीज़ किया जा रहा है।'

स्टाफ़िंग फ़र्म टीमलीज़ डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा, 'आईटी कंपनियों में मैनेजर लेवल के लोगों को हटाया जा रहा है और उन कर्मचारियों को रखा जा रहा है जो सीधे काम करते हैं, ताकि वर्कफ़ोर्स को व्यवस्थित किया जा सके और क्षमता बढ़ाई जा सके। एआई, क्लाउड और डेटा सिक्योरिटी जैसे नए क्षेत्रों में भर्तियां बढ़ी हैं, लेकिन जिस तेज़ी से नौकरियां जा रही हैं, उस अनुपात में नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फ़ैसला देश की सॉफ़्टवेयर इंडस्ट्री में 'स्किल गैप' को भी उजागर करता है।

बिज़नेस सलाहकार कंपनी 'ग्रांट थॉर्नटन भारत' से जुड़े अर्थशास्त्री ऋषि शाह के मुताबिक़, 'जनरेटिव एआई के कारण प्रॉडक्टिविटी में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। यह बदलाव कंपनियों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने वर्कफ़ोर्स स्ट्रक्चर पर फिर से विचार करें और देखें कि संसाधनों को एआई के साथ काम करने वाली भूमिकाओं में कैसे लगाया जाए।'

नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ़्टवेयर एंड सर्विसेज़ कंपनीज़ (नैसकॉम) का अनुमान है कि 2026 तक भारत को 10 लाख एआई प्रोफ़ेशनल्स की ज़रूरत होगी, लेकिन फ़िलहाल देश के 20 फ़ीसदी से भी कम आईटी प्रोफ़ेशनल्स के पास एआई की स्किल है।

तकनीकी कंपनियां नए एआई टैलेंट तैयार करने के लिए ट्रेनिंग पर ज़्यादा ख़र्च कर रही हैं, लेकिन जिनके पास ज़रूरी स्किल नहीं है, उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है।

एआई के आने से पैदा हुए बदलावों के अलावा, वैश्विक निवेश बैंकिंग फ़र्म जेफ़रीज़ का कहना है कि टीसीएस का ऐलान भारत के आईटी सेक्टर में 'ग्रोथ संबंधी व्यापक चुनौतियों को भी दिखाता है।' जेफ़रीज़ ने एक नोट में लिखा, 'वित्त वर्ष 2022 से इंडस्ट्री स्तर पर नेट हायरिंग कमज़ोर रही है, इसके पीछे की वजह मांग में लंबे समय से चल रही गिरावट है।'

अमेरिका में आईटी सेवाओं की मांग पर भी असर पड़ा है, जो भारतीय सॉफ़्टवेयर कंपनियों की कुल कमाई का आधा स्रोत है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ़ नीतियों ने इस पर असर डाला है।

हालांकि, टैरिफ़ मुख्य रूप से सामानों को प्रभावित करते हैं। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि कंपनियां टैरिफ़ से जुड़ी अनिश्चितताओं और अपनी ग्लोबल सोर्सिंग रणनीतियों के आर्थिक प्रभाव का आकलन करते हुए आईटी पर होने वाले अतिरिक्त ख़र्च को रोक रही हैं।

'एआई तकनीक अपनाने की वजह से अमेरिकी कंपनियां लागत कम करने के लिए दबाव बना रही हैं, जिससे बड़ी आईटी कंपनियों को कम स्टाफ़ के साथ काम करना पड़ रहा है।'

इसका असर अब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में दिखने लगा है, जो कभी भारत के आईटी बूम के केंद्र थे। एक अनुमान के मुताबिक़, पिछले साल इस सेक्टर में क़रीब 50 हज़ार लोगों की नौकरियां गई थीं। भारत की शीर्ष छह आईटी कंपनियों में नए कर्मचारियों की संख्या में 72 प्रतिशत की कमी आई।

इसका असर भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, जो हर साल वर्किंग फ़ोर्स में शामिल होने वाले लाखों युवा ग्रेजुएट्स के लिए पर्याप्त नौकरियां बनाने में पहले से ही संघर्ष कर रही है। मज़बूत मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर की ग़ैर-मौजूदगी में, इन सॉफ़्टवेयर कंपनियों ने 1990 के दशक में भारत को दुनिया का बैक ऑफ़िस बनाया और ये लाखों नए आईटी वर्कर्स के लिए पसंदीदा विकल्प थीं। इन्होंने एक नया समृद्ध मध्यम वर्ग तैयार किया, जिसने शहरों में विकास को बढ़ावा दिया और कारों के साथ घरों की मांग बढ़ाई। लेकिन जब स्थिर और अच्छी तनख़्वाह वाली नौकरियां कम हो रही हैं, तब भारत की सर्विस सेक्टर आधारित आर्थिक वृद्धि पर सवाल उठने लगे हैं।

कुछ साल पहले तक भारत की बड़ी आईटी कंपनियां हर साल क़रीब 6 लाख नए ग्रेजुएट्स को नौकरी देती थीं। टीमलीज़ डिजिटल के अनुसार, पिछले दो साल में यह संख्या घटकर करीब 1.5 लाख रह गई है। दूसरे उभरते हुए सेक्टर जैसे फ़िनटेक स्टार्टअप्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बाक़ी युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं।

भारत के कई बड़े बिज़नेस लीडर्स ने इन रुझानों के आर्थिक असर पर चिंता जताई है।

टीसीएस के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण भारत के बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डी मुथुकृष्णन ने 'एक्स' पर लिखा कि 'घटता आईटी सेक्टर कई सहायक सेवाओं और उद्योगों पर नकारात्मक असर डालेगा, रियल एस्टेट को नुक़सान पहुंचाएगा और प्रीमियम खपत को बड़ा झटका देगा।' कुछ महीने पहले मोटर टेक्नोलॉजी कंपनी एटॉमबर्ग के संस्थापक अरिंदम पॉल ने लिंकडइन पर चेतावनी दी थी कि एआई भारत के मध्यम वर्ग पर गंभीर असर डाल सकता है। उन्होंने लिखा था, 'आज मौजूद क़रीब 40-50 फ़ीसद व्हाइट-कॉलर नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। इसका सीधा मतलब होगा मध्यम वर्ग और खपत की कहानी का अंत।'

एआई के बदलावों के साथ भारतीय टेक कंपनियां कितनी जल्दी कदम मिलाती हैं, इसी पर तय होगा कि भारत दुनिया में तकनीकी क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा या नहीं। इससे यह भी तय होगा कि भारत अपने मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ाकर जीडीपी की रफ़्तार बनाए रख सकेगा या नहीं।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित रिपोर्ट के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मेरे ही लहू पर गुज़र-औक़ात करो हो
मुझ से ही अमीरों की तरह बात करो हो

दिन एक सितम एक सितम रात करो हो
वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो

हम ख़ाक-नशीं तुम सुख़न-आरा-ए-सर-ए-बाम
पास आ के मिलो दूर से क्या बात करो हो

हम को जो मिला है वो तुम्हीं से तो मिला है
हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो हो

यूँ तो कभी मुँह फेर के देखो भी नहीं हो
जब वक्त पड़े है तो मुदारात करो हो

दामन पे कोई छींट न ख़ंजर पे कोई दाग़
तुम क़त्ल करो हो कि करामात करो हो

बकने भी दो 'आजिज़' को जो बोले है बके है
दीवाना है दीवाने से क्या बात करो हो।

- कलीम आजिज़

● 'मालेगांव ब्लास्ट' केस में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सातों आरोपी बरी

6 की गई थी जान

बाइक प्रज्ञा की और कर्नल आरडीएक्स लाए यह दोनों बातें साबित नहीं हुईं

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा- हम एनआईए कोर्ट के

फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज एके लाहोटी ने फैसला सुनाया।

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता

लेकिन दोषसिद्धि नैतिक आधार पर नहीं हो सकती

एनआईए की स्पेशल कोर्ट में जज एके लाहोटी ने कहा-आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दोषसिद्धि नैतिक आधार पर नहीं हो सकती। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जिस बाइक पर कथित तौर पर बम रखा गया था, वह प्रज्ञा की थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा दोपहिया वाहन के चेसिस का सीरियल नंबर पूरी तरह से बरामद नहीं किया गया था, इसलिए अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि ठाकुर ही उस दोपहिया वाहन की मालिक थीं। कोर्ट ने कहा- इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया था या बम बनाया था। हालांकि, पुरोहित और एक अन्य आरोपी अजय राहिरकर के बीच अभिनव भारत के अधिकारियों के रूप में वित्तीय लेन-देन हुआ था, लेकिन पुरोहित ने उस पैसे का इस्तेमाल केवल अपने घर और एलआईसी पॉलिसी के निर्माण में किया था, किसी आतंकवादी गतिविधि में नहीं। अन्य आरोपियों के साथ साजिश का कोई सबूत नहीं।

महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी बन गए बड़ा खतरा!

● 42 हजार फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के खिलाफ ऐक्शन

● फणनवीस सरकार ने कहा- 15 अगस्त तक सारे होंगे कैंसल

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐक्शन तेज हो गया है। महाराष्ट्र में जिन लोगों ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हैं उन्हें रद्द करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की जांच के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया है। महाराष्ट्र में बनाई गई यह टास्क फोर्स जांच करेगी कि राज्य में ऐसे कितने बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं। जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, उन्हें रद्द करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 15 अगस्त तक पूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र रद्द करेगी। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार 15 अगस्त तक ऐसे 42,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाणपत्र रद्द कर देगी। यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जांच जारी है। राजस्व और स्वास्थ्य विभागों को इस मामले पर मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला इस साल की शुरुआत में सुर्खियों में आया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि 3997 जन्म प्रमाणपत्र जाली दस्तावेजों का जरिए बनवाए गए हैं। ये फर्जी प्रमाणपत्र बांग्लादेशी नागरिकों को जारी किए गए। किरीट सोमैया ने इसके दस्तावेज भी दिखाए। उनके आरोप के बाद मालेगांव में तैनात दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मार्च में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बड़ी जानकारी दी थी।

प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री यादव की नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात

म.प्र. में निवेश संबंधी किये जा रहे प्रयासों की दी जानकारी

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की और पुष्प-गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्यप्रदेश की उपलब्धियों एवं नवाचार पर केंद्रित पुस्तिका 'विरासत से विकास की राह' भेंट की। पुस्तिका में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन, जनजाति कल्याण, किसान कल्याण, नारी शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, शहरी विकास, अधोसंरचना विकास, पर्यटन एवं संस्कृति संरक्षण और पर्यावरण संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा शामिल है।

दुबई-स्पेन की निवेश यात्रा से कराया अवगत- प्रधानमंत्री श्री मोदी

को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए की गई दुबई एवं स्पेन की यात्रा में मिली सफलता की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदेश की साढ़े 8 करोड़ आबादी को हमेशा मिलता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी के आशीर्वाद से विकसित भारत @ 2047 के विजन में मध्यप्रदेश भी अपना पूरा योगदान देगा।

केन्द्रीय कैबिनेट ने इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी

महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर से श्रीशैलम (आंध्रप्रदेश) और रामेश्वर (तमिलनाडु) तक ज्योतिर्लिंग यात्रा होगी सहज

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी देने के लिए आभार माना है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई इस मंजूरी से मध्यप्रदेश को विशेष लाभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन को मंजूरी मिलने से प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा सहित नागपुर (महाराष्ट्र) को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने से प्रदेश के महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर से श्रीशैलम (आंध्रप्रदेश) और रामेश्वरम (तमिलनाडु) तक ज्योतिर्लिंग यात्रा और सहज एवं आसान होगी। परियोजना के क्रियान्वयन से हर साल 5.3 करोड़ लीटर डीजल की बचत के साथ ही 10 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित होगी। साथ ही एक हजार 206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स लागत में भी बचत संभावित होगी।

सावलकोट से शुरुआत...

सिंधु जल संधि का फुल एंड फाइनल करने में जुटा भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले दिन भारत ने सिंधु जल संधि को सिर्फ रोका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत इस समझौते के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने के मूड में आ चुका है। बुधवार को भारत ने चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी कर दिया है। सामरिक नजरिए से यह भारत का बहुत बड़ा कदम है, जिसके तहत सिंधु

नदी के जल को वह अपने हित में इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि, सिंधु जल संधि की आड़ में पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से ही यह प्रोजेक्ट दशकों से लंबित पड़ा हुआ था। पहलगाम हमले के एक दिन बाद भारत ने 23 अप्रैल, 2025 को सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया था और 30 जुलाई, 2025 को 1,856 मेगावाट के सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया।

पाकिस्तान को भारत से बड़ी कूटनीतिक चोट

अब जब सावलकोट प्रोजेक्ट को फास्ट-ट्रैक में रखने का फैसला ले लिया गया है, कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तानी की परेशानी और बढ़ सकती है। भारत यह कदम इसलिए उठा पाया है, क्योंकि वह सिंधु समझौते को राष्ट्रहित में रोक चुका है। पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत ने यह रणनीति अपना ली है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश को भी वह आतंकवादियों की श्रेणी में ही रखेगा। यह पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने 1960 ने भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु समझौता करवाया था, वह पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में बताया जाता था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 1 अगस्त 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

यूपी में मर्ज नहीं होंगे 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूल

शिक्षा मंत्री बोले-

जो हुए हैं, उन्हें रद्द करेंगे, टीचर का एक पद समाप्त नहीं होगा

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा- एक किमी से अधिक दूरी पर किसी भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी स्कूल में 50 से अधिक छात्र हैं तो उसे भी मर्ज नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं। उनको अनपेयर यानी उनका मर्जर कैंसिल किया जाएगा। साथ ही, मर्जर में स्कूल की जो बिल्डिंग खाली हो रही हैं, उनमें बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका शुरू की जाएगी। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे।

लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने दावा किया कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। न ही एक भी टीचर का पद समाप्त किया जाएगा। दरअसल, यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों का मर्ज करने का फैसला किया था। अब तक 10827 स्कूल का मर्जर हुआ है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने मर्जर के आदेश को सही बताया था। इसके बाद सीतापुर के ही कुछ अन्य बच्चों ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सीतापुर के 210 में से 14 स्कूलों का मर्जर रोक दिया था। एक किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक छात्र संख्या वाले जो स्कूल मर्ज हुए हैं, उन्हें फिर अनपेयर किया जाएगा। यानी, मर्जर कैंसिल किया जाएगा। सरकार शिक्षा भर्ती के खिलाफ नहीं है।

कबूतरों को दाना चुगाना बन सकती है परेशानी, सेहत के लिए भी खतरा

● बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दाना डालने वालों पर एफआईआर करने की दी परमीशन

मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। यह मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। 30 जुलाई को जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को शहर के कबूतरखानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने का निर्देश भी दिया। दरअसल, 3 जुलाई को इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट

ने बीएमसी को किसी भी पुराने विरासती कबूतरखाने को ध्वस्त करने से रोक दिया था, लेकिन कहा था कि दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती। पल्लवी पाटिल, स्नेहा विसारिया और सविता महाजन ने याचिका में दावा किया था कि बीएमसी का यह काम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करता है। अनुमति न मिलने के बावजूद लोग कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं। अब यह स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि पिछले आदेश में याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। नगर निगम के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जा रहा है। कानून की अवहेलना की जा रही है। हम बीएमसी को ऐसे किसी भी व्यक्ति और समूहों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई 2025 को विधायी सदन में घोषणा की कि मुंबई के सभी 51 कबूतरखानों को तत्काल बंद किया जाएगा। उसी दिन बीएमसी को निर्देशित किया गया कि सारे फीडिंग स्पॉट बंद होने के बाद 500 का जुर्माना लगाया जाए।

राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे

● अमेरिकी टैरिफ पर संसद में बोली मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क (टैरिफ) के प्रभावों का आंकलन किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गोयल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई तथा उद्योग जगत के सभी हितधारकों की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क और जुर्माना लगाने की बुधवार को घोषणा की। गोयल ने सदन में दिए वक्तव्य में अमेरिका के साथ बातचीत के बारे में जानकारी दी और कहा कि दोनों पक्षों के बीच दिल्ली और वाशिंगटन में आमने-सामने की चार बैठकें हुईं तथा कई बार डिजिटल माध्यम से बातचीत हुई। उनका कहना था, हालिया घटनाक्रम के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सभी हितधारकों से संवाद कर उनके आंकलन की जानकारी ले रहा है।

भोपाल को बनाया जाए सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार का आदर्श शहर : जस्टिस सप्रे

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति अध्यक्ष के साथ जिला सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक

भोपाल (नप्र)। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे ने कहा है कि भोपाल में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में संगठित प्रयासों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित सभी संबंधित विभागों को गंभीरता, लगन और समर्पण भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर आगामी 3 माह में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा संबंधी समिति भोपाल को इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे की अध्यक्षता में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय भोपाल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव, नगर निगम आयुक्त श्री हरेन्द्र नारायण, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती अंजू अरुण कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती ईला तिवारी एवं एडीएम श्री अंकुर मेश्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने कहा कि हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाए, सीट बेल्ट उपयोग के प्रति जागरूकता लाई जाए, शराब पीकर वाहन चलाने वालों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए ताकि सड़कों पर छोटे वाहनों का दबाव कम हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग सहित सभी शासकीय कर्मचारी वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट/हेलमेट का उपयोग करें। स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने मीडिया से जन-जागरूकता अभियान को गति देने में सहयोग का भी आग्रह किया।

न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने भोपाल जिले के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन एवं उनके सुधार कार्यों, चालानी कार्रवाई, जन-जागरूकता अभियानों और अन्य नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और किसी की गलती से निर्दोष की जान न जाए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने निर्देश दिए कि वाहनों की फिटनेस की नियमित जांच की जाए, ड्राइविंग टेस्ट में सख्ती बरती जाए, बीमा और लाइसेंस की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए तथा ओवरलोडिंग पर रोक के लिए विशेष कार्रवाई की जाए। सड़कों पर मानक गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए राहवीर योजना और कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

श्री सप्र ने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस बड़ी संस्थाओं से अपील करे कि वे अपने कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधाएं, जैसे बसें आदि, उपलब्ध कराएं जिससे सड़कों से वाहनों का अत्यधिक दबाब कम हो। उन्होंने जिले के नागरिकों से भी आग्रह किया कि बच्चों को बचपन से ही सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि भोपाल जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें नवाचार और जन-जागरूकता अभियान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

एक देश-एक चुनाव से जीडीपी 1.5 फीसदी तक बढ़ सकती है

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक देश-एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की छठी बैठक बुधवार को संसद भवन एनेक्सी में हुई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और इकोनॉमी की प्रोफेसर डॉ. प्राची मिश्रा ने अपनी राय रखी। न्यूज एजेंसी सूत्रों के हवाले बताया कि दोनों ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को आर्थिक रूप से फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि इससे चुनावों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अपने साझा प्रेजेंटेशन में दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी में यह बढ़ोतरी 4.5 लाख करोड़ रुपए की होगी। हालांकि, चुनावों के बाद ज्यादा खर्च होने से राजकोषीय घाटा (सरकार का खर्च) भी करीब 1.3 प्रतिशत बढ़ सकता है। बार-बार चुनाव होने से मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ता है।

तारीख नोट कर लीजिए! आज से मिलेगी मुफ्त बिजली

बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 125 यूनिट से कम पर फायदा

पटना (एजेंसी)। नीतिश कुमार की ओर से किए गए ऐतिहसिक ऐलान का फायदा मिलना शुरू होने वाला है। तो आप भी नए कैलेंडर की 1 अगस्त की तारीख को टिक कर लीजिए, क्योंकि अब 125 यूनिट बिजली की बचत का फायदा इसी महीने के बिजली बिल पर नजर आने वाला है। ये राहत बिहार के 125 यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाले परिवारों के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप 125 यूनिट से कम बिजली उपयोग करते हैं तो आपका बिजली बिल 'शून्य' होगा। अब ऐसे उपभोक्ताओं का बिल शून्य होगा। बिहार के 1.86 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए अगस्त का महीना बेहद खास होने वाला है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अब हर महीने 125 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इस घोषणा का सीधा लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगा अगस्त महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई में कैबिनेट से पारित इस योजना का लाभ 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए अगस्त में जारी होने वाला बिल सीधे 125 यूनिट की कटौती के साथ तैयार होगा। वहीं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों को 125 यूनिट तक कोई रिचार्ज नहीं करना होगा। अगर रिचार्ज पहले ही कर चुके हैं, तो उस यूनिट की राशि उनके शेष बैलेंस में जुड़ जाएगी। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक, 1.67 करोड़ उपभोक्ता हर महीने औसतन 125 यूनिट या उससे कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे में ये उपभोक्ता अब शत-प्रतिशत सब्सिडी का सीधा लाभ उठा पाएंगे। शहरी उपभोक्ताओं को करीब 550 रुपये प्रति माह की बचत होगी। वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं को करीब 306 रुपये प्रति माह का फायदा मिलेगा। बिहार सरकार की ओर से दी गई यह सहायता सभी ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए समान लागू होगी। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ सभी को मिलेगा।

अकबर ने सामने सॉफ्ट चेहरा पेश किया, पीछे की क्रूरता

● महाकवि तुलसीदास को याद कर बोले योगी आदित्यनाथ

चित्रकूट (एजेंसी)। धार्मिक नगरी चित्रकूट में संत तुलसीदास के जयंती समारोह (तुलसी जयंती) में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्ष पूर्व जब इस गांव की स्थिति शायद साधनों के अभाव और कठिनाइयों से ग्रस्त रही होगी, ऐसे समय में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया और बाल्यावस्था में ही प्रभु श्रीराम के चरणों में स्वयं को समर्पित

कर दिया। उन्होंने कहा कि उस कालखंड में जब अकबर का साम्राज्य विस्तार पर था और दरबार में जगह पाने की होड़ थी, तब तुलसीदास जी ने खुद को किसी दरबारी की सेवा में नहीं बल्कि केवल प्रभु श्रीराम की भक्ति में समर्पित किया। सीएम योगी ने कहा कि जब देश के राजे-रजवाड़े विदेशी आक्रांता की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, उस समय तुलसीदास जैसे संत भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम के रूप में जनचेतना को जाग्रत कर रहे थे।

- **राम नाम के स्मरण से धन्य होगा जीवन-** मुख्यमंत्री ने रामजन्मभूमि आंदोलन के संदर्भ में जगतगुरु रामभद्राचार्य के योगदान की भी चर्चा की और कहा कि जब प्रमाण मांगे गए तो उनके सामने महाराज जी ने धाराप्रवाह बोलना शुरू किया, तो वे भौंचक्के रह गए। यही भगवान की सिद्धि है। उन्होंने मुरारी बापू द्वारा आगामी रामकथा आयोजनों को प्रयागराज, अयोध्या और काशी में किए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि राम नाम का स्मरण कर हर कोई अपने जन्म को धन्य करेगा।
- **जिनका जीवन विवादित, वही संतों को विवादों में घसीट रहे-** मुख्यमंत्री ने संतों को विवादों से जोड़ने वाले लोगों पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर पूज्य संतों को विवादित करने की कोशिश करते हैं। जिनका जीवन विवादित है, वही ऐसा करते हैं।

मार्निंग वॉक में सीएम से मेल और हो गया खेल!

● तमिलनाडु में पूर्व सीएम ने छोड़ा बीजेपी का साथ

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन उससे पहले ही राज्य की राजनीति करवटें लेने लगी है। एक नाटकीय घटनाक्रम में गुरुवार सुबह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके से निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम, जिन्हें

ओपीएस के नाम से भी जाना जाता है, ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने की घोषणा की। बुधवार को चेन्नई में मॉर्निंग वॉक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री और डीएके प्रमुख एमके स्टालिन संग मुलाकात और चर्चा के कुछ घंटे बाद ओ पनीरसेल्वम ने इसका ऐलान किया। ऐसी चर्चा थी कि ओपीएस भाजपा से नाराज चल रहे थे।

ट्रम्प ने दिखाई आंख, इंडिया को बताया डेड इकोनॉमी

कहा-भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबें, मुझे क्या

वॉशिंगटन (एजेंसी)। भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया। उन्होंने कहा- भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबें, मुझे क्या। एक दिन पहले ट्रम्प ने 1 अगस्त 2025 से भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। अभी भारत पर अमेरिका का टैरिफ सामान के हिसाब से औसतन 10 फीसदी के आसपास है। डेड इकोनॉमी का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जो रुक गई हो या तेजी से गिर रही हो। इसमें व्यापार, निवेश, और विकास लगभग ठप हो जाते हैं, और लोग इसे 'मरी हुई' अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें हालात से उबरने की क्षमता नहीं रहती। डोनाल्ड ट्रम्प ने 30 जुलाई को ऐलान किया कि भारतीय सामानों पर अमेरिका में 1 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लगेगा। उन्होंने रूस से व्यापार के चलते भारत पर पेनल्टी लगाने की बात भी कही। राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी (मृत अर्थव्यवस्था) बताने पर कहा- मुझे खुशी हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है।

- **6 भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी ऐक्शन-** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार देर रात ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें 6 भारतीय कंपनियां भी हैं। इसके अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हॉन्गकॉन्ग की 3, तुर्किये और रूस की 1-1 कंपनी भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की। मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरानी मूल के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद यूएई के रास्ते मंगवाए। ईरान इस पैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। मंत्रालय ने इसे अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया है। ईरान पर 2018 से प्रतिबंध है।

मोदी कैबिनेट के रेलवे-किसानों के लिए 6 बड़े फैसले

● किसान संपदा का बजट अब बढ़ाकर 6,520 करोड़ किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं। वहीं चार फैसले नॉर्थ-ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। वहीं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों (कोऑपरेटिव सोसाइटीज) को मजबूत किया जाएगा।

स्नातक में प्रवेश के लिए अब 14 अगस्त तक होगा अतिरिक्त सीएलसी चरण

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये अतिरिक्त सीएलसी चरण की तिथि में वृद्धि की है। अब 14 अगस्त तक अतिरिक्त सीएलसी चरण जारी रहेगा, पूर्व में यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।

मंत्रालय में आज होगा राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान

भोपाल (नप्र)। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत 'वन्देमातरम' एवं राष्ट्रगान 'जन गण मन' का गायन 1 अगस्त को प्रातः 10:15 बजे किया जाएगा। वर्षा होने की स्थिति में उक्त गायन मंत्रालय क्रमांक-1 स्थित पांचवी मंजिल कक्ष क्रमांक 506 में होगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का आयोजन पटेल पार्क में किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने अमर शहीद सरदार उधम सिंह के बलिदान दिवस पर अर्पित की श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अमर शहीद उधम सिंह ने अपने दृढ़ संकल्प से जलियांवाला बाग में निर्दोष निहत्थे देशवासियों की जान लेने वाले माइकल ओ-डायर को मौत के घाट उतारा था। सरदार उधम सिंह का जीवन युवाओं के लिए संकल्प शक्ति और मातृभूमि की भक्ति का प्रेरणादायक प्रतीक है।

सीएम ने गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर किया पुण्य-स्मरण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रामभक्त गोस्वामी तुलसीदास को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को तुलसी जयंती की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परम पावन श्रीरामचरित मानस, विनय पत्रिका सहित अन्य कृतियों के माध्यम से तुलसीदास ने प्रभु श्रीराम की अनन्य भक्ति का मार्ग दिखाया, जो अनंतकाल तक जनमानस का कल्याण करेगा।

उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने वंचित वर्ग की आवाज को किया मुखर : डा यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उनका पुण्य-स्मरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रेमचंद ने गोदान, गबन, निर्मला जैसी अमूल्य रचनाओं से हिन्दी साहित्य को समृद्धि प्रदान की। साथ ही हमेशा कमजोर और वंचित वर्ग की आवाज को मुखर किया। प्रेमचंद का कृतित्व नव प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करता रहेगा।

भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश

1 अगस्त से हेलमेट नहीं पहना तो पंप से पेट्रोल नहीं ले सकेंगे

भोपाल (नप्र)। शहर में अब दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट पहने किसी भी पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप से पेट्रोल अथवा सीएनजी नहीं भरवा सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि भोपाल जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है।

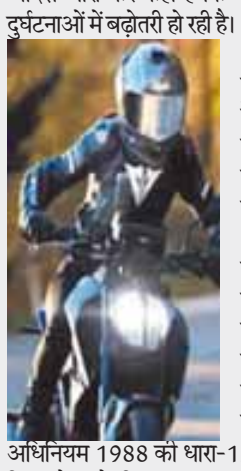

इन दुर्घटनाओं में मौत का बड़ा कारण हेलमेट नहीं पहनना है। उपर्युक्त प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। बता दें कि मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दोपहिया वाहन सवारी और वाहन चालक आईएसआई मार्क हेलमेट पहनेंगे। आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

नहाते समय नाले में डूबे बच्चे, दो शव निकाले

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा में नहाने गए दो बच्चे नाले में डूब गए। दोनों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। कोलाढाना क्षेत्र में बने सिवरेज पॉइंट के पास गुलाबरा क्षेत्र के छह बच्चे गुरुवार को खेलने के लिए कोलाढाना क्षेत्र में पहुंचे थे।

खेलते-खेलते वे सिवरेज पॉइंट के पास बने बोदरी नाले में उतरकर नहाने लगे। इसी दौरान अचानक दो बच्चे पानी के तेज बहाव में डूब गए। अन्य चार बच्चों ने घटना को देखकर शोर मचाया, जिससे स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने तुरंत डूबे बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। काफी देर की मशक्कत के बाद एक बच्चे का शव बाहर निकाला जा सका। वहीं दूसरे का शव निकालने के लिए एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद दूसरे शव को भी निकाला गया। कोतवाली थाना निरीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि डूबे दोनों बच्चे गुलाबरा क्षेत्र के निवासी हैं। हालांकि अभी परिजनों की जानकारी ली जा रही है। बच्चों की पहचान नहीं हो सकी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर सौजन्य भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

माँ का दूध अमृत है, हर नवजात को मिले जीवन की यह पहली सुरक्षा : मंत्री सुश्री भूरिया

भोपाल (नप्र)। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। एक अगस्त से प्रारंभ हो रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री सुशील निर्मला भूरिया ने प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और सभी नागरिकों का आह्वान किया है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध और छह माह तक केवल माँ का दूध देना अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को घर-घर, गाँव-गाँव पहुँचाएं और माताओं को सही समय पर सही जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाएं।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि माँ का दूध नवजात के लिए अमृत है। उन्होंने कहा कि स्तनपान नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की पहली एवं सबसे महत्वपूर्ण नींव है। पहला गाढ़ा दूध (कोलोस्ट्रम) शिशु को न केवल संक्रमण से बचाता है बल्कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। साथ ही माँ और शिशु के बीच पहले रिश्ते को भी सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने चिंता जताई कि आज भी कई क्षेत्रों में परंपरागत भ्रांतियों के कारण नवजात को शहद, घुट्टी या पानी दिया जाता है, जो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समाज में पोषण और स्वास्थ्य परिवर्तन की है अग्रदूत

महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केवल सेविका नहीं, बल्कि समाज में पोषण और स्वास्थ्य परिवर्तन की अग्रदूत हैं। वे माताओं की भरोसेमंद मार्गदर्शक हैं और उनके प्रयासों से ही संभव हो पाएगा कि हर माँ को स्तनपान के महत्व की जानकारी और परिवार का सहयोग प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केवल महिला की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज का सामूहिक दायित्व है। इस विश्व स्तनपान सप्ताह में यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नवजात माँ के दूध से वंचित न रहे।

मालेगांव के फैसले पर एमपी में संतों ने बांटी मिठाई

उमा के छलके आंसू, कहा- प्रज्ञा को बहुत प्रताड़ित किया गया

- बीजेपी के नेता बोले- फैसला सनातन के पक्ष में
- कांग्रेस ने कहा- महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए

भोपाल (नप्र)। मालेगांव बम विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले ने मध्यप्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। भाजपा नेताओं ने इसे सत्य और सनातन की जीत बताया। कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। साधु-संतों ने भी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा को बहुत प्रताड़ित किया गया।

पूर्व सीएम बोलीं- मैं इतनी खुश हूं कि मेरे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं - पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा, मैं इतनी खुश हूं कि मेरे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। जब प्रज्ञा नासिक जेल में थीं, मुझे एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से पता चला कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया था। मैं उनसे मिलने गई थी जब कोई और नहीं जाता था। जब मैं उनसे मिली तो मैं रोई... जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, वह किसी भी महिला के लिए सहन करना बहुत मुश्किल है।

मंत्री टेटवाल बोले- दूध का दूध और पानी का पानी हो गया- मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय विचारधारा का कार्यकर्ता है और न्यायालय पर भरोसा करता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हमारी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तथाकथित सरकारों द्वारा झूठे मुकदमे लगाए थे। कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई।

वीडी शर्मा बोले- भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव चला- बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा बोले- मालेगांव ब्लास्ट में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, उन्हें आज अदालत ने बरी कर दिया है। उस समय कांग्रेस के नेताओं, खासतौर पर दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने मध्यप्रदेश में 'भगवा आतंकवाद' का एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की थी।

आज के इस निर्णय ने साबित कर दिया कि कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसी कथित कहानियां गढ़ीं, ताकि हिंदुत्व पर प्रहार किया जा सके और उसे बदनाम किया जा सके। यह साफ हो गया है कि उन्होंने झूठे आरोप लगाकर निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रची थी। क्या चिदंबरम, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेतृत्व इस पर माफी मांगेंगे?

उन्होंने एक झूठे 'भगवा आतंकवाद' के नाम पर न केवल लोगों को प्रताड़ित किया, बल्कि पूरे एक विचार और संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की। इसका जवाब अब उन्हें देना चाहिए।

मंत्री शुक्ला बोले- फैसला सनातन के पक्ष में आया है- नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि कुछ तथाकथित लोगों ने प्रज्ञा जी पर आरोप लगाया था। न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। प्रज्ञा जी हमारी सनातन की एक रक्षक हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से जो फैसला आया है, वह सनातन के पक्ष में आया है।

मालिनी गौड़ बोलीं- सत्य की विजय हुई है- इंदौर विधानसभा क्रमांक-4 की विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि कांग्रेस को एक साध्वी को इतनी यातनाएं दीं। इसे भगवा आतंकवाद का नाम दिया। कांग्रेस को साध्वी का श्राप लगा है। सत्य की विजय हुई है।

उषा ठाकुर बोलीं- सुनियोजित षड्यंत्र में फंसाया गया

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा सत्य की जीत हुई है। प्रज्ञा जी ने जो कष्ट सहे उन पर आज न्याय मिला। हम जानते थे कि हमने अपराध नहीं किया है और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया गया है तो एक दिन सभी बाइज्जत बरी होंगे।

अर्चना चिटनीस- न्याय व्यवस्था पर श्रद्धा बढ़ी

बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने कहा- 17 साल के संघर्ष के बाद जो निर्दोष लोग पीड़ित होते रहे, प्रताड़ित होते रहे, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, आज उन्हें न्याय मिला है। ऐसे फैसलों से भारत की न्याय व्यवस्था पर श्रद्धा और भी बढ़ती है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा- फैसला है सच है या झूठ, फैसला तो दे दिया

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कोर्ट का फैसला है। सब को स्वीकार होगा। फैसला है सच है या झूठ, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया।

आरिफ मसूद बोले- सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ब्लास्ट केस में अपील की थी।

जयवर्धन सिंह- गांधी के हत्यारों की तारीफ, देश की सोच नहीं

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा- आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसमें भगवा कहना गलत है। मेरी निजी सोच है कि जो लोग गोडसे का समर्थन करते हैं, कम से कम लोकतंत्र में उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। साध्वी प्रज्ञा कई बार गांधी जी के हत्यारों की तारीफ कर चुकी हैं, जो हमारे देश के सोच के विपरीत है।

साधु-संत बोले- सनातन धर्म की जीत हुई

उज्जैन से संत विशाल दास ने कहा आज सत्य की जीत हुई है, आज सनातन धर्म की जीत हुई है। हमारा सनातन धर्म, जिसे कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की थी, उन्होंने भगवा को आतंकवाद का प्रतीक बताने की कोशिश की थी आज उसी भगवा को न्याय मिला है।

हमारा भगवा आतंकवाद का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह उस भावना का प्रतीक है, जो शास्त्रों में वर्णित है,

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत।

कॉलेज संचालक के घर पर चला बुलडोजर

व्यापमं के आरोपी सोनू पचौरी के इशारे पर कार्रवाई का लगाया आरोप

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कोलार इलाके स्थित ग्राम बंजारी में एक्स्टॉल कॉलेज के संचालक ज्ञानेंद्र भटनागर के घर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चला दिया। गेट बाउंड्रीवॉल को भी तोड़ दिया गया। ज्ञानेंद्र ने इस पूरी कार्रवाई को अवैधानिक और गुंडों के इशारे पर कब्जे की मंशा से किया जाने वाला बताया है।

पूरी कार्रवाई 18 जुलाई की है, जिसकी शिकायत ज्ञानेंद्र की ओर से बुधवार को एडिशनल पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी के कार्यालय तक पहुंची। तब पूरा मामला उजागर हुआ। ज्ञानेंद्र का आरोप है कि जिस हिस्से को अवैध बताकर तोड़ा गया है, वहां सोनू पचौरी ने अपने गुंडो की तैनाती कर दी है। कार्रवाई के बाद से ही उन्हें उन्हीं की घर और जमीन पर नहीं जाने दिया जा रहा है।

ज्ञानेंद्र भटनागर के मुताबिक जहां कार्रवाई की गई वहां उनका बीस साल पुराना निर्माण था। आस पास की एक एकड़ जमीन उन्हीं की है। सोनू पचौरी और उसके गुंडो ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे निर्माण को ध्वस्त किया है। जिससे करीब 15-20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कार्रवाई के दौरान सोनू के गुंडे पुलिस की मौजूदगी में मेरे बेटे को धमकाते रहे। पुलिस भी उन्हीं की भाषा बोलकर हमें धमकाती रही। थाने शिकायत करने पहुंचे तो शिकायत नहीं सुनी गई।

पुराने गुंडे पर कब्जे का आरोप

कार्रवाई निगम ने की है तो किस हक से सोनू के गुंडों ने कार्रवाई के बाद नियम विरुद्ध बताकर तोड़े गए मकान के हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इस बात का जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। सोनू पुराना गुंडा है, व्यापम घोटाले का मास्टर माइंड है और लंबे समय तक जेल काट चुका है। वे लगातार हमें धमका रहा है, हमारी जमीन छोड़ने का दबाव बना रहा है। लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। टीटी नगर इलाके में भी सोनू गोलीकांड कर चुका है। उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं।

पुलिसकर्मी पर भी धमकाने के आरोप

ज्ञानेंद्र की ओर से बताया गया कि कार्रवाई की दौरान एक पुलिसकर्मी ने उनके बेटे को धमकाया है, इसका वीडियो उनके पास है। वहीं नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी मधुसूदन तिवारी ने बताया कि कार्रवाई नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन टीम ने की है। नियम विरूद्ध बने हिस्से को तोड़ा गया है।

टीआई बोले- पुलिस पर लगे आरोप निराधार

कोलार थाने के टीआई संजय सोनी ने बताया कि पुलिस पर लगे बदसलूकी के आरोप निराधार हैं। नगर निगम ने कार्रवाई के लिए लिखत में बल की मांग की थी। कानून व्यस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई के दौरान बल को मौके पर भेजा गया था।

बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस का नौरोजाबाद और रूपोंद स्टेशनों पर ठहराव शुरू

भोपाल (नप्र)। यात्रियों की सुविधा और लंबे समय से की जा रही क्षेत्रीय मांगों को देखते हुए रेल प्रशासन ने बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस का दो और स्टेशनों पर ठहराव शुरू कर दिया है। अब यह गाड़ी नौरोजाबाद और रूपोंद स्टेशनों पर भी रुकेगी। यह ठहराव स्थायी रूप से लागू किया गया है, जिससे आसपास के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह सुविधा शुरू की जा चुकी है। इससे यात्रियों को मुख्य स्टेशनों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और उन्हें अपने नजदीकी स्टेशन से ही सीधी ट्रेन सेवा मिल रही है।

गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस

नौरोजाबाद स्टेशनः रात 2:53 बजे आगमन, 2:55 बजे प्रस्थान

रूपोंद स्टेशनः सुबह 3:41 बजे आगमन, 3:43 बजे प्रस्थान

गाड़ी संख्या 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस

रूपोंद स्टेशनः रात 8:32 बजे आगमन, 8:34 बजे प्रस्थान

नौरोजाबाद स्टेशनः रात 9:35 बजे आगमन, 9:37 बजे प्रस्थान

इन दोनों छोटे लेकिन महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव मिलने से क्षेत्र के ग्रामीण और कस्बाई यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वह भविष्य में भी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के ठहराव और सुविधाओं में विस्तार करता रहेगा। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान रेल नियमों का पालन करें और सुविधाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करें।

निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूर्ण करें और शीघ्र सेवा प्रदाय करें : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के पात्र प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के दिए निर्देश

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विषयों पर समन्वय और समयबद्धता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, इसके लिए निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूर्ण करें और इन पूर्ण कार्यों से शीघ्र सेवा प्रदाय की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने गुरूवार को विभागीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की वृहद समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, संचालक प्रोजेक्ट श्री नीरज कुमार सिंह एवं एमडी एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन प्रस्तावों की वृहद समीक्षा की। बताया गया कि एनएचएम के 3 विकास के 179, भवन के 81, स्थापना के 72 और अस्पताल प्रशासन के 34 कुल यानि 369 प्रस्तावों में से

198 का परीक्षण किया जा चुका है और इनमें से 113 प्रस्ताव उपयुक्त पाए गए हैं। एसएचसी के 51, पीएचसी के 12, सीएचसी के 9 उन्नयन प्रस्ताव सहित एसएचसी के 37 नवीन प्रस्ताव तथा जिला अस्पताल के 3 प्रस्ताव शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शेष प्रस्तावों के शीघ्र परीक्षण एवं पात्र प्रस्तावों में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रक्रियाधीन कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे राशि का समय से उपयोग सुनिश्चित कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने बांड पोस्टिंग चिकित्सकों की कार्यस्थल में उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की और विधिवत सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं सहायक चिकित्सक की लोक सेवा आयोग और ईएसबी के माध्यम से की जा रही भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अक्टूबर 2025 तक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्त औपचारिकताओं को समय से पूर्ण किया जाये और भर्ती प्रक्रिया की वरिष्ठ अधिकारी सतत निगरानी करें।

पचमढ़ी के ट्रेनिंग सेंटर में भूटान आर्मी जवान की मौत

तालाब में डूबा, विदेश मंत्रालय जाएगी रिपोर्ट, 14 देशों के जवान संगीत सीखने आते हैं

नर्मदापुरम (नप्र)। हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित आर्मी एजुकेशन कोर (एईसी) के करियप्पा कंपनी परिसर में बुधवार दोपहर करीब 2:20 बजे भूटान आर्मी के 27 वर्षीय जवान शिवांग गेलसेन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इंटरनेशनल मामला होने की वजह से शव को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां गुरुवार को पोस्टमार्ट्म किया गया।

पुलिस के अनुसार मृतक शिवांग गेलसेन, पिता सोनम, रॉयल भूटान आर्मी में आरक्षक (रैंक - चुमा) के पद पर कार्यरत था। वह 7 मई 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक की 5 महीने की ट्रेनिंग पर पचमढ़ी आया था। यहां वह एईसी के आरएम कोर्स में बैंड सीखने की ट्रेनिंग ले रहा था।

खाने के बाद तालाब के पास गया- पचमढ़ी थाना प्रभारी अनूप सिंह उईके ने बताया कि बुधवार को दोपहर का खाना खाने के बाद शिवांग सेंटर परिसर के तालाब के पास गया था। वह कभी-कभार मछली पकड़ने भी जाता था। उसी दौरान वह अचानक तालाब में गिर गया और डूबने लगा। उसने बचाव के लिए आवाज लगाई।

साथियों ने बचाने की कोशिश की- शिवांग की आवाज सुनकर उसके साथी तेजसिंह समेत अन्य जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे और उसे तालाब से बाहर निकालकर तुरंत आर्मी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्ट्म भोपाल में हुआ- पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। चूंकि मामला विदेशी सेना के जवान से जुड़ा था, इसलिए प्रक्रिया के तहत शव को भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट

मामला अंतरराष्ट्रीय होने के कारण सेना और जिला प्रशासन दोनों सतर्क हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और संबंधित रिपोर्ट रॉयल भूटान आर्मी व विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी।

संगीत की ट्रेनिंग के लिए देश में एकमात्र सेंटर

देश में संगीत के सैनिकों की ट्रेनिंग की एकमात्र जगह है पचमढ़ी। यहीं है आर्मी म्यूजिक स्कूल। 75 साल पुराने यह म्यूजिक स्कूल एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री म्यूजिक स्कूल है। पहले नंबर पर आता है लंदन का मिलिट्री म्यूजिक स्कूल।

अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिजिटल म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए पचमढ़ी में बने भारतीय सेना के मिलिट्री म्यूजिक विंग को आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। 1997 में सबसे बड़े मिलिट्री बैंड के लिए इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ था।यहां देश के 60 म्यूजिक बैंड और 11 हजार से ज्यादा म्यूजिक सोल्जर तैयार हुए हैं।

श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार और नेपाल से ट्रेनिंग लेने आते हैं

भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, माली, भूटान, म्यांमार और नेपाल जैसे 14 देशों के अफसर-जवान भी यहां म्यूजिक की ट्रेनिंग लेते हैं। सैनिकों के लिए यहां 3 महीने से लेकर 148 हफ्तों के दस कोर्स चलाए जाते हैं। सेना के अलावा नौसेना, वायुसेना के साथ पुलिस, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अपने सैनिक-अफसरों को यहां ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं।

संपादकीय

ट्रंप टैरिफ या ब्लैकमेल?

समझना कठिन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी टैरिफ टेरर नीति के तहत भारत पर सचमुच 25 फीसदी टैरिफ और जुर्माना लगाने जा रहे हैं या फिर यह केवल हमे ब्लैकमेल करने का एक तरीका है, जिससे भारत दबाव में आकर अमेरिकी शर्तों को मान ले। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि कल ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुनिया को बताया कि वो भारत पर 25 फीसदी टैरिफ और रूस के साथ आर्थिक और सैन्य रिश्ते कायम रखने के लिए उस पर जुर्माना भी लगाने जा रहे हैं। नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। इस आदेश का भारत के बाजारों और कूटनीति के पहले दिखने के पूर्व ही अमेरिका से यह सफाई आई कि अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं हुआ है। जबकि ट्रंप की डेडलाइन 1 अगस्त थी। भारत अभी भी यही कह रहा है कि टैरिफ को लेकर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। दरअसल ट्रंप हर गंभीर मामले में अपनी जल्दबाजी और किसी हद तक छिछोरे अंदाज में जो घोषणाएं करते हैं और थोड़ी देर बाद ही पलटी मार जाते हैं, उससे उनकी विश्वसनीयता रसातल में जा चुकी है। हकीकत यही है कि ट्रंप को दुनिया में अब कोई गंभीरता से नहीं लेता। यह समझना ही मुश्किल है कि अमेरिका किस मामले में गंभीर है और किस मामले में नहीं है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध रूकवाने के लिए भारत के जरिए रूस पर दबाव डलवाना चाहते हैं। लेकिन यह असंभव है। भारत अमेरिका को खुश करने के लिए रूस से दशकों पुराने रिश्तों को तिलांजलि नहीं दे सकता। अमेरिका की तुलना में भारत के लिए रूस का भरोसा ज्यादा कीमती है। जब मीडिया ने भारत पर टैरिफ के बारे में ट्रंप से सवाल किया तो उनका जवाब था कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं। जबकि भारत साफ कर चुका है कि टैरिफ को लेकर भारत देशहित में ही काम करेगा और आगे की रणनीति तय करेगा। आगे क्या होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता परंतु भारत में ट्रंप के प्रस्तावित 25 टैरिफ और जुर्माने के प्रभावों का गंभीरता से अध्ययन और उसके संभावित परिणामों पर विचार जारी है। इस बीच देश में विपक्षी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ और पेनाल्टी भी लगा दी है। मोदी ने ट्रंप को गले लगाया। लेकिन उसका सिला ये है। यह भारत की विदेश नीति की घोर नाकामी है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत लगातार जारी है। कुछ क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों में मतभेद हैं। जैसे कि भारत जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड फ़सलें (जैसे सोयाबीन और मक्का) आयात करने का विरोध कर रहा है और घरेलू डेयरी बाज़ार विदेशी कंपनियों के लिए खोलना नहीं चाहता। भारत आयात पर सर्वाधिक औसतन 17 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाता है। वहीं अमेरिका का टैरिफ़ दो अप्रैल से पहले 3.3 फीसदी ही था। गौरतलब है कि साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत का लगभग 46 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष (ट्रेड प्लस) था। साल 2024 में भारत की औसत टैरिफ़ दर 11.66 प्रतिशत थी। अर्थशास्त्री मिताली निकोर कहती हैं कि अब वास्तविक टैरिफ 35 फ़ीसदी हो गया है। यह तब तक लगेगा, जब तक हम रूस से तेल लेते रहेंगे। बढ़े टैरिफ का जेम एंड जूलरी, कपड़ा, मोबाइल व टेलिकॉम सेक्टर पर होगा। सिटी रिसर्च का अनुमान है कि टैरिफ़ लगने से भारत को सालाना 700 करोड़ डॉलर का घाटा होगा। वास्तविक घाटा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है।

सदन में बहस का अभिप्राय

देश का बौद्धिक वर्ग सदन में बहस को देश के लोकतंत्र के लिए, देश के विकास के लिए, देश की दूरगामी रणनीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है लेकिन दूर-दराज़ बैठे आदिवासी समाज के लोग, मेहनतकश, मजदूर व प्रत्येक दिन अपने जीवन से जूझते हुए लोग इस बहस के बारे में नहीं जानते। उनके यहाँ छोटे से कर्मचारी ही साहेब होता है। जिलाधिकारी भी साहेब होता है। वह प्रधानमंत्री व मंत्रियों को अपना भगवान और मंत्रियों को देवी-देवता मानता है। किसी भी राज्य का यह चरित्र समाज के निचले तबके के लिए अपना आज तक नहीं बन सका। सबसे अहम् बात यह है कि क्षेत्र से चुनकर आया हुआ प्रतिनिधि भी उनको सदन में आकर लगभग भूल जाता है और अपने लिए नई तैयारी करने लगता है। आज देश की जो गति है, जो दुर्दशा है, उसका कारण यही है।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

मानसून सत्र दिल्ली में चल रहा है। इस बीच भारत के सभी सांसद दिल्ली में हैं और संसद के दोनों सदनों में जोरदार बहस कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटना मानसून सत्र की शुरुआत में घटी कि भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ का इस्थीपा हो गया। दोनों सदनों के सांसद हतप्रभ रह गए। यद्यपि इसकी शुरुआत में ही प्रधान मंत्री ने विजयोत्सव नाम दिया। यह पहलगाम घटना के बाद पहला संसद सत्र है, इसलिए प्रधान मंत्री ने इसको विजयोत्सव कहा।

सत्र में बहस ही देश के विभिन्न योजनाओं को जमीं प्रदान करती हैं। विभिन्न बिल से देश हित में निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए देश की लगभग डेढ़ अरब की आबादी इंतज़ार करती है। देश के सभी लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि देश की महापंचायत हमारे हित में निर्णय ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के प्रथम दिवस कहा कि मैं ये जरूर कहूंगा राजनीतिक दल अलग-अलग है, हर एक का अपना एक एंजेडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले ना मिले, लेकिन देशहित में मन जरुर मिले। एक अच्छे लोकतांत्रिक देश की पहचान यही होती है कि देश हित में फैसले लेने के लिए मतभेद को भुलाकर लोकतंत्र में बसने वाले सभी लोगों के लिए निर्णय लिया जाये।

यह सत्र विशेष रूप से पहलगाम बहस के लिए ज्यादा जाना जाएगा। इसके सन्दर्भ में भी प्रधान मंत्री ने पहले दिन स्पष्ट किया कि पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़कर के देशहित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधियों ने विश्वभ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए, और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रीय हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं, और इसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। इन दोनों बिन्दुओं को ध्यान में रखकर यदि इस सत्र की बात की जाए तो बहुत सारे प्रश्न मन में कौंधते हैं। कुछ ऐसे सवाल जब ऐसा लगता है कि आखिर यह बहस हो ही क्यों रही है? इस बहस के अभिप्राय क्या हैं? इस बहस से क्या निकलने वाला है? क्या इस महापंचायत में बैठे लोग बहस के नाम पर कुछ अतीत को कुरेदना चाहते हैं? क्या इस बहस के बाद कोई ऐसा भी हल निकलकर सामने आएगा, जिससे भारत की डेढ़ अरब की आबादी को यह विश्वास होगा कि देश सही दिशा में जा रहा है?

भारत की इसी संसद में कुछ समय पहले संविधान पर बहस हुई थी। डॉ। आंबेडकर को लेकर व संविधान को लेकर न जाने कितनी तरह की बातें की गयी। बहुत से आर्ग्युमेंट आये लेकिन उस बहस का क्या नतीजा निकला, यह भारत की डेढ़ अरब की आबादी कभी नहीं जान सकेगी। तो सवाल यह है कि सदन की बहस मीडिया हॉउस की बहस के लिए होते हैं और इससे कॉर्पोरेट घराने विभिन्न डिबेट, डिस्कशन करवाकर अपनी कमाई करते हैं? अब देश की जनता यह मन में ही सही, लेकिन सवाल करने लगी है कि सदन में बहस के अभिप्राय क्या हैं?

देश का बौद्धिक वर्ग सदन में बहस को देश के लोकतंत्र के लिए, देश के विकास के लिए, देश की दूरगामी रणनीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है लेकिन दूर-दराज़ बैठे आदिवासी समाज के लोग, मेहनतकस, मजदूर व प्रत्येक दिन अपने जीवन से जूझते हुए लोग इस बहस के बारे में नहीं जानते। उनके यहाँ छोटे से कर्मचारी ही साहेब होता है। जिलाधिकारी भी साहेब होता है। वह प्रधान मंत्री व मंत्रियों को अपना भगवान और मंत्रियों को देवी-देवता मानता है। किसी भी राज्य का यह चरित्र समाज के निचले तबके के लिए अपना आज तक नहीं बन सका। सबसे अहम् बात यह है कि क्षेत्र से चुनकर आया हुआ प्रतिनिधि भी उनको सदन में आकर लगभग भूल जाता है और अपने लिए नई तैयारी करने लगता है। आज देश की जो गति है, जो दुर्दशा है, उसका कारण यही है। भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ बिजली आज तक नहीं पहुँची, आज़ादी के 75 वर्ष बाद, उसका जिम्मेदार कौन है और कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? देश में पांच किलो अनाज अब स्टैटस सिम्बल बन रहा है, यह भी देश की गति है। सदन में बहुत सी बहसों के बीच यह जो प्रश्न हैं, वे अन्दर तक हिला देते हैं।

सदन में केवल एक दूसरे पर छीटाकशी फैशन बन चुकी है। कोई अपनी न गलती मानने को तैयार होता है और न ही अपने दायित्व का निर्वाह भविष्य में दुरुस्त करने की जिम्मेदारी बताता है। तुमने ऐसा किया, फला ने ऐसा किया, फल ने ऐसा किया था, तुम्हारे समय में ऐसा हुआ, तुम्हारे समय में तो ऐसा हुआ था, हद है, यह कौन सी बहस है। देश की दुर्दशा इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता अपनी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं और एक दूसरे को लांक्षित करते हुए थकते नहीं हैं। एक बोलता, दूसरा स्वीकार करता। दूसरा बोलता, पहला स्वीकार करता। जो गलतियाँ हो रही हैं, उसकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए प्रतिबद्धताएं बनतीं, तो भारत सच में विश्व में अपनी विशेष पहचान के लिए जाना जाता। देश में तो बस राजनीतिक रोटियां सेंकने की होड़ लगी हुई है। इसलिए इस देश का बंटाधार हुआ है।

मानसून सत्र में देश की ताकत संसद सदस्य हैं। देश का संविधान है। देश के राजनेताओं की अपनी इच्छाशक्ति है। इस सत्र में भी वही हुआ जो अन्य सत्र में होता रहा है। इसलिए इस सत्र का भी कुछ विशेष लाभ मिलेगा, इस पर जनता को भरोसा इस बात पर है कि इस बहस का कुछ हल निकलने वाला नहीं है। युद्ध, संघर्ष व वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य की शक्ति कई पैमाने पर आंकलन की मांग करती है। यथा कुछ पहलुओं को ही रेखांकित करें तो देश की आर्थिक शक्ति, संप्रभुता की रक्षा में आने वाली रुकावटें, देश की विदेश निति व डिप्लोमेसी, हमारी आतंरिक ताकत, जनता का मानस यह सब बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं।

यदि इन सब पर ज्यादा समझदारी से दुरुस्त न करने की जिद हो तो सदन में बहस की कोई ज़रूरत है ही नहीं और न ही देश की जनता को गुमराह करने की आवश्यकता है। इस मानसून सत्र से देश को बड़ी उम्मीदें थीं लेकिन जिम्मेदारियों से भागती संसद, सानास्द कम्युनिटी निश्चय ही जनता को निराश करने पर तुली हुई है। ऐसी बहसें किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं हैं और न ही इससे किसी प्रकार की संप्रभुता को बल मिलने वाला है।

ऐसे में, बहस के अभिप्राय पर पूरी संसद को विचार करने की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है। यह देश कब सुधरेगा और कब सही दिशा में अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग करेगा यह लम्बे समय से प्रतीक्षित है।

जब गुनहगार छूटते हैं और पीड़ित रह जाते हैं

मुद्दा

प्रियंका सौरभ

लेखक शोधार्थी हैं।

मुंबई में वर्ष 2006 में हुए लोकल ट्रेन धमाके देश के इतिहास की सबसे भयानक आतंकी घटनाओं में से एक थे। सात जगहों पर ट्रेनों में बम विस्फोट कर के 189 लोगों की जान ली गई और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला केवल मानव शरीरों पर नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया था। पूरा देश सन्न रह गया था। भय, आक्रोश और असहायता के बीच एकमात्र आशा थी - न्याय की। परंतु जब लगभग 19 वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के 12 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब एक बार फिर यह प्रश्न गूंजने लगा कि क्या हमारे देश में पीड़ितों को कभी न्याय मिल भी पाता है?

यह निर्णय केवल एक अदालती प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला था जिसमें जांच एजेंसियों की निष्क्रियता, अभियोजन की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप की मिलीजुली साजिश वर्षों से न्याय को घुटनों पर लाने का कार्य कर रही है। किसी भी न्यायालय का कार्य तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देना होता है। लेकिन जब जांच ही लचर हो, जब सबूत इतने कमजोर हों कि अदालत उन्हें स्वीकार ही न करे, तो फिर न्यायालय भी विवश हो जाता है।

इस मामले में आरोपियों को सज़ा न मिल पाने का दोष न्यायालय पर मढ़ना आसान है, लेकिन वास्तव में जिम्मेदार वे अधिकारी हैं जिन्होंने इस गंभीर आतंकी हमले की जांच को हल्केपन और जल्दबाज़ी से अंजाम दिया। कई आरोपियों के कबूलनामे जबरन करवाए गए, जो कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं हैं। विस्फोट स्थलों से फॉरेंसिक साक्ष्य समय पर एकत्रित नहीं किए गए। गवाहों की सुरक्षा को नज़रअंदाज़ किया गया। चार्जशीट्स में विरोधाभासी बातें सामने आईं और अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सका।

इन सबका परिणाम यह हुआ कि वे लोग जो सालों से दोषियों को सज़ा दिलाने की उम्मीद में अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगी। क्या इस देश में किसी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या पीड़ित परिवारों की आंखों के आँसू, उनकी टूटती उम्मीदें और उनके जीवन की असुरक्षा हमारी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी नहीं?

यह कोई पहला मामला नहीं है जहां न्याय व्यवस्था ने पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफलता दिखाई हो। भोपाल गैस त्रासदी, हाशिमपुरा नरसंहार, 1984 सिख दंगे, और निठारी हत्याकांड - यह सभी उदाहरण हैं जहां या तो दोषी छूट गए या न्याय मिलने में इतनी देर हुई कि उसका कोई अर्थ ही नहीं बचा। यह सबूत हैं कि हमारी न्यायिक प्रणाली में समय, साक्ष्य और सत्य - तीनों की कमी होती जा रही है।

न्याय केवल अदालत में फैसले देने की प्रक्रिया नहीं है, वह समाज के उस विश्वास की रीढ़ है जो शासन और प्रशासन पर टिका होता है। यदि बार-बार अपराधी बच निकलें, यदि आतंकवादी छूट जाएं, और यदि पीड़ित सालों अदालतों की सीढ़ियां चढ़ते रहें तो वह विश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

मुंबई ट्रेन धमाके की जांच जिस प्रकार से की गई, वह बताता है कि हमारी जांच एजेंसियां न केवल तकनीकी रूप से कमजोर हैं, बल्कि वे राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए अभिशप्त भी हैं। भारत में जांच का ढांचा ब्रिटिशकालीन मानसिकता पर आधारित है, जिसमें अपराधी को पकड़ने से ज़्यादा उसे 'दिखाने' पर ज़ोर होता है। और जब मामला आतंकवाद से जुड़ा हो, तो कई बार बेकसूरों को पकड़ कर जनता के गुस्से को शांत करने की कोशिश की जाती है। इससे असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं जाता, और सारा केस अदालत में दम तोड़ देता है।

इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जो चिंता पैदा करते हैं। जैसे - जांच में देरी, सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह न होना, अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य न होना, और गवाहों का मुकर जाना। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम न्याय की उम्मीद करें, तो यह केवल छलावा होगा।

क्या न्यायपालिका को केवल मौन दर्शक बने रहना चाहिए? क्या उसका कोई दायित्व नहीं कि वह जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए? जब अदालतों ने कई अन्य मामलों में विशेष जांच दल गठित किए हैं, तो फिर इस गंभीर मामले में क्यों नहीं? न्यायिक सक्रियता केवल राजनैतिक मामलों या नागरिक अधिकारों तक ही सीमित क्यों?

वास्तव में न्याय प्रणाली को समयबद्ध, वैज्ञानिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक सम्पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले तो अभियोजन विभाग को पुलिस से अलग कर स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन किसी राजनीतिक दबाव या पुलिस की एकतरफा जांच का हिस्सा नहीं बनेगा।

दूसरे, गवाह सुरक्षा कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आतंकवाद जैसे मामलों में गवाहों को धमकाना बहुत आम है, जिससे वे अदालत में बयान बदल देते हैं। तीसरे, जांच एजेंसियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि वे डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों को प्रभावी रूप से इकट्ठा कर सकें।

चौथे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाकर ऐसे मामलों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से करनी चाहिए, ताकि पीड़ितों को 19 साल तक न्याय की प्रतीक्षा न करनी पड़े। और पांचवां, यदि कोई जांच एजेंसी जानबूझकर कमजोर चार्जशीट बनाती है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है- मीडिया की भूमिका। मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा। जब कोई मामला अदालत में हो, तब मीडिया द्वारा किसी को दोषी या निर्दोष घोषित कर देना, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल से गवाहों पर दबाव बनता है और जनता का पूर्वग्रह उभरता है। यह भी कारण है कि न्याय अपने नैतिक स्वरूप से दूर होता जा रहा है।

आख़िर में यही कहा जा सकता है कि न्याय केवल कागज़ी प्रक्रिया नहीं है, वह एक जीवंत विश्वास है, जो प्रत्येक नागरिक के मन में इस सोच के साथ पलता है कि कोई उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता। जब यह विश्वास टूटता है, तब देश की आत्मा घायल होती है।

मुंबई ट्रेन धमाकों के पीड़ितों के साथ जो हुआ, वह केवल एक अदालती मामला नहीं है ङ्क वह पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि यदि अब भी हमने अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारा, तो अगली बार फिर कोई धमाका होगा, फिर निर्दोष मारे जाएंगे, फिर कोई माँ न्याय की भीख मांगेगी, और फिर कोई अदालत कहेगी - साक्ष्य नहीं मिले।

इस बार अगर हम नहीं जागे, तो इतिहास बार-बार यह प्रश्न पूछेगा - क्या भारत में न्याय केवल सुविधा भर है?

अकेलापन

संध्या अग्रवाल

सामाजिक संरचना की अनदेखी परछाई

वो महिला जो हर दिन मंदिर जाती है, पड़ोसियों को नमस्ते कहती है, हर उत्सव में भाग लेती है, दरअसल भीतर से कितनी अकेली है, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं होता। अकेलापन एक ऐसी चुप्पी है जो दिखती नहीं, पर हर कोने में पसरी होती है। यह कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक गंभीर चूक है, जिसे हमने लंबे समय से अनदेखा कर रखा है। हमने एक ऐसी सामाजिक संरचना तैयार की है जिसमें रिश्तों का दिखावा है, पर गहराई नहीं, सहभागिता का भ्रम है, पर साथ नहीं।

हमारे चारों ओर लोगों की भीड़ है, पर संवाद नहीं। डिजिटल दुनिया में हम लगातार जुड़े तो रहते हैं, लेकिन भीतर की बातें कहने-सुनने वाले रिश्ते धीरे-धीरे मिटते जा रहे हैं। पहले आँगन साझा होते थे, दीवारें पतली होती थीं और दुःख-सुख एक-दूसरे से बाँटे जाते थे। आज हर किसी के पास अपने कमरे हैं, अपने मोबाइल हैं और अपनी दुनिया है जिसमें कोई दूसरा दाख़िल नहीं हो सकता। ऐसे में जब जीवन की शाम होने लगती है, तब सबसे ज़्यादा शोर करता है अकेलापन – बिना बोले, बिना दिखे।

अकेलापन उम्र की किसी सीमा से नहीं बँधा होता। वह बच्चों को भी हो सकता है जो माता-पिता की व्यस्तता में उपेक्षित हो जाते हैं। युवाओं को भी, जो कैरियर की दौड़ में खुद को मशीन बना बैठते हैं। लेकिन सबसे गहराई से यह बुज़ुर्गों और स्त्रियों के जीवन में दिखता है। जिन स्त्रियों ने जीवनभर परिवार के लिए जीया, उनकी ज़रूरतें पूरी कीं, उनके सपनों को सींचा – वही एक दिन चुपचाप एक कोने में बैठी पाई जाती हैं। उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है, पर सुनने वाला कोई नहीं। उनके भीतर भावनाओं का समंदर होता है, पर समाज उसे देखता ही नहीं।

समस्या यह नहीं कि लोग व्यस्त हैं, समस्या यह है कि हमने भावनात्मक ज़रूरतों को कोई महत्व देना ही छोड़ दिया है। किसी का अकेलापन तब और गहराता है जब समाज उसे 'मज़बूत', 'स्वतंत्र' या 'समझदार' मानकर उससे संवाद करना भी बंद कर देता है। हम भूल जाते हैं कि भावनाओं का संबंध उम्र या परिस्थिति से नहीं, इंसान की मूल ज़रूरत से होता है। साथ, समझदारी, सहभागिता – ये सब जीवन की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिन्हें हमने आधुनिकता के नाम पर खो दिया है।

आज का समाज जितना तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, उतना ही भावनात्मक रूप से पीछे हट गया है। मन की बात अब मन में ही रह जाती है। रिश्ते औपचारिक हो गए हैं और संवाद सीमित। अकेलापन धीरे-धीरे मन की मिट्टी को बंजर बना देता है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है, जिसकी चपेट में आकर व्यक्ति अवसाद, अनिद्रा और कभी-कभी आत्मघात तक की ओर बढ़ जाता है।

इसका समाधान सिर्फ दवाइयाँ या थेरेपी नहीं हैं, बल्कि एक संवेदनशील समाज है। ऐसा समाज जहाँ लोग एक-दूसरे को सुनने का समय निकालें, बेमक़सद मिलने बैठें, दिल की बातें कहें और समझें। जहाँ वृद्धजनों को केवल जिम्मेदारी नहीं, संवाद मिले। जहाँ महिलाएँ केवल कर्तव्य नहीं, आत्मीयता पाएँ। जहाँ युवा केवल सलाह नहीं, साथ पाएँ। एक ऐसा माहौल जहाँ अकेलापन अपराध नहीं, एक अनुभव माना जाए – जिसे साझा किया जा सकता है, समझा जा सकता है, बाँटा जा सकता है।

शायद हमें अपने बच्चों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि अकेले रहना सीखो, बल्कि यह सिखाना चाहिए कि किसी को अकेला मत छोड़ो। समाज का असली सौंदर्य उसकी भावनात्मक एकजुटता में है, न कि केवल भौतिक प्रगति में। किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपे सन्नाटे को पहचानना भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी हम सबकी है – आपके, मेरे, हम सबकी।

कभी-कभी अकेलेपन से लड़ने के लिए कोई बड़ी कोशिश नहीं चाहिए होती। बस एक फ़ोन कॉल, एक चाय का निमंत्रण, या यूँ ही बिना किसी कारण के किसी का हाल पूछ लेना भी बहुत कुछ बदल सकता है। क्योंकि अक्सर अकेलापन तब टूटता है, जब कोई पास आकर कहता है – 'मैं हूँ ना।'

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

हास्य व्यंग्य

डॉ. हरि जोशी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

प्रातः स्मरणीय पेट!

जा कुछ के पेट तो कभी भरते ही नहीं है, फिर भी मनुष्यों की प्रातः स्मरणीय समस्या एक है, 'पेट कैसे भरना?' अनेक नेताओं, अफसरों का कभी भरा है ? चलो मान लिया, भर गया,अब उससे भी बड़ी मुसीबत, सुबह-सुबह पेट को खाली करना। 'योगाचार्यों ने तक,इसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा माना है। यह एक वैश्विक समस्या है। 'सुबह पेट कैसे साफ़ हो ?' इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंसों द्वारा तक दिशानिर्देश दिए गए हैं। यद्यपि समस्या सुलझाने के लिए तरह-तरह के चूरन बाज़ार में उपलब्ध हैं। कुछ लोग तम्बाकू,बीड़ी सिगरेट,को इसके लिए रामबाण दवा मानते हैं।

उस दौर में, नगरवासियों की 'नवाब साहेब का पेट' ही मुख्य समस्या थी। लोग कान लगाकर,सुबह-सुबह तोप की प्रतीक्षा करते।लेस की तोप चल गई,याने नवाब साहब का पेट साफ़ हो गया। तोप एक ही खुशी में तो छूटती थी ?

इधर तोप छूटी ,उधर दुखी जन अपने अपने घरों से महल के लिए छूटते। नबाब साहब पीने खाने के तो बड़े शौकीन थे, पर उनका पेट बड़ा बदमाश था। सुबह घंटों मशक्कत कराने के बाद भी,खाली होने का नाम नहीं लेता था। वह दिन भर पीने खाने में कोई कंजूसी नहीं करते थे, भले ही सुबह-सुबह पेट खाली कराने में कड़ी मेहनत लगती थी' दिन भर तो वह जमकर सूतते, किन्तु सुबह-सुबह उनका पेट खाली करा लेना राज्य की बड़ी समस्या थी। सुबह-सुबह अनेक गरीब-गुरबे तक भगवान से याचना करते देखे जाते थे या खुदा ,नवाब साहब का पेट जल्दी साफ़ कर ,ताकि वह खुश होकर, हमें इनाम इकराम बांटें, हमारी अर्जी सुनें?'नवाब साहब ही दुखी रहेंगे तो हम पीड़ित लोग कहाँ जायेंगे? उनका पेट साफ़ करना,बड़े मालगोदाम को उलीच लेने जैसा बड़ा उपक्रम था। खुद के लिए ही नहीं,अर्दलियों और समूचे राज्य की वह प्रातःस्मरणीय समस्या थी। घंटों वर्जिश करने वाले नौकर चाकर मशक्कत में लगे रहते थे किन्तु बदमाश पेट टस से मस नहीं होता था। प्रजा के सौभाग्य से जिस दिन उनका पेट कम मशक्कत से जल्दी खाली हो जाता, उस दिन वे तुरही बजवाते,ढोल नगाड़े, बैंड बजवाते। तोप चलाकर शहर भर को सूचित करते कि अब जनता दुखी न रहे, खुशी का बहुप्रतीक्षित क्षण आ चुका है।'

अब वह गरीबों को उपहार देते,दुखी जनों की शिकायतें सुनते। दुखीजन भगवान को धन्यवाद देते कि उनकी याचना आज जल्दी सुन ली गई।

पुराने समय में ऐसे बिरले व्यक्तित्व होते होंगे, अब तो जगह जगह दफ्तरों में नए- नए नवाब आ चुके हैं,जिनके पेट कभी भरते ही नहीं। पचता नहीं पर खाते जाते हैं। भगवान जाने सुबह-सुबह वे क्या गुल खिलाते होंगे ?

लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर विशेष

स्वराज व स्वधर्म के प्रति स्वाभिमान के जागरणकर्ता

सुरेन्द्र शर्मा

लेखक भाजपा मध्य प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं।

भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन का जब भी स्मरण किया जाएगा उसमें भारतीय स्वराज एवं स्वधर्म के प्रति स्वाभिमान का जागरण करने के लिए बाल गंगाधर तिलक उपाख्य लोकमान्य तिलक को सर्वप्रथम स्मरण किया जायेगा। वह भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक,स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकप्रिय नेता थे उनके नाम के आगे लोकमान्य लगाया जाता है यह वह उपनाम है जो उन्होंने अपने कर्तत्व से जनता के दिलों में स्थान बनाकर प्राप्त किया था। लोकमान्य तिलक ने ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान 'पूर्ण स्वराज' की मांग उठाई थी इसके लिए उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक भी कहा जाता है 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा' का नारा देने वाले भी लोकमान्य तिलक ही थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक लोकमान्य तिलक हैं ।

बाल गंगाधर तिलक सिर्फ एक लोकप्रिय नेता ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृत,हिंदू धर्म गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान थे उनका पूरा जीवन एक आदर्श है और भारत के स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है ।

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था तिलक के पिताजी का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान और प्रख्यात शिक्षक थे उनकी माता जी का नाम पार्वतीबाई गंगाधर था वह एक वह एक विदुषी महिला और आदर्श ग्रहणी थी तिलक के पिता अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे उन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तक लिखी जो प्रकाशित हुई तथापि वह अपने पुत्र की शिक्षा पूरी करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे 1872 में श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक का निधन हो गया।

बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के कारण मात्र 16 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गए उन्होंने तब भी बिना विचलित हुए अपनी शिक्षा जारी रखी और पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर ही आयोजित मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। वे डेक्कन कॉलेज में भर्ती हो गए फिर उन्होंने 1876 में बी ए ऑनर्स की परीक्षा वहीं से पास की सन 1879 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री पूर्ण की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक निजी विद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता का मार्ग चुना।

बालगंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुये लेकिन कभी भी कांग्रेस का नेतृत्व करने का अवसर उन्हे नहीं दिया गया क्योंकि वह समझौता वादी नहीं सामर्थ्यवान नेता थे इतिहासकार उन्हे उग्रवादी विचारों का नेता कहते हैं वह कांग्रेस में लाला लाजपत राय विपिन चंद्र पाल के साथी थे इस तिकड़ी को लाल-बाल-पाल की उग्रवादी तिकड़ी कहा जाता है।।

सन् 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग, अकाल और भूकंप का संकट एक साथ आ गया लेकिन दुष्ट अंग्रेजों ने ऐसे में जबरन लगान की वसूली जारी रखी इससे तिलक का मन उद्वेलित हो गया तिलक ने 'महामारी अधिनियम 1897' के प्रावधानों के खिलाफ लेख लिखा और जनता को संगठित कर आंदोलन छोड़ दिया।

अपने लेख में तिलक ने कमिश्नर वाल्टर और चार्ल्स रेंड को निशाना बनाया तिलक के लेख से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के दो युवा चाफेकर बंधुओं ने रेंड की हत्या कर दी ब्रिटिश सरकार ने तिलक को हत्या के लिए उकसाने और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया इस मामले की सुनवाई और सजा से उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली तिलक को 18 महीने की सजा सुनाई गई जहां उन्होंने पहली बार स्वराज के विचारों को विकसित किया।

तिलक जी ने जेल में अध्ययन का क्रम जारी रखा और बाहर आकर फिर से आन्दोलन में कूद गये।

तिलक जी एक अच्छे पत्रकार भी थे,उन्होंने अंग्रेजी में 'मराठा'तथा मराठी में 'केसरी' साप्ताहिक अखबार निकाला। इसमें प्रकाशित होने वाले विचारों से पूरे महाराष्ट्र और फिर देश भर में स्वतन्त्रता और स्वदेशी की ज्वाला भभक उठी। युवक वर्ग तो तिलक जी का दीवाना बन गया। लोगों को हर सप्ताह केसरी की प्रतीक्षा रहती थी। अंग्रेज इसके स्पष्टवादी सम्पादकीय आलखों से तिलमिला उठे।

बंग-भंग के विरुद्ध हो रहे आन्दोलन के पक्ष में तिलक जी ने खूब लेख छापे।

30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड को अपना निशाना बनाते

हुए एक बम विस्फोट किया था इसमें दो ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों ने खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया इस गिरफ्तारी के खिलाफ लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार 'केसरी' में लिखा उनके इस लेख ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए 3 जुलाई 1908 को अंग्रेजों ने तिलक को गिरफ्तार कर लिया और 23 जुलाई 1908 को उन्हें अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई उन्हें बर्मा की मंडाले जेल में रखा गया सृजन धर्मी तिलक ने यहां 400 पेज का गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा ।

जो आज भी गीता पर एक श्रेष्ठ टीका मानी जाती है। इसके माध्यम से उन्होंने देश को कर्मयोग की प्रेरणा दी।

बालगंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे जबकि वह अपना अध्यात्मिक तथा वैचारिक पथ प्रदर्शक गणेश वासुदेव जोशी को मानते थे जिन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी।

तिलक जी समाज सुधारक भी थे। वे बाल-विवाह के विरोधी तथा विधवा-विवाह के समर्थक थे। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में वे सरकारी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जनजागृति के लिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव व शिवाजी उत्सव की परम्परा शुरू की, जो आज विराट रूप ले चुकी है।

स्वतंत्रता आन्दोलन में उग्रवाद के प्रणेता तिलक जी का मानना था कि स्वतंत्रता भीख की तरह माँगने से नहीं मिलेगी वर्ष 1916 में उन्होंने नारा दिया - 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और में उसे लेकर ही रहूंगा'।

वे वृद्ध होने पर भी स्वतन्त्रता के लिए भागदौड़ में लगे रहे। जेल की यातनाओं तथा मधुमेह से उनका शरीर जर्जर हो चुका था। मुम्बई में अचानक वे निमोनिया बुखार से पीड़ित हो गये। अच्छे से अच्छे इलाज के बाद भी वे सँभल नहीं सके और एक अगस्त, 1920 को मुम्बई में ही उन्होंने अन्तिम साँस ली।

महात्मा गांधी ने उन्हे आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये डेक्कन एजुकेशन सोसायटी और फर्गुसन कॉलेज की भी स्थापना की थी।

बाल गंगाधर तिलक एक महान राष्ट्रवादी,समाज सुधारक और जन नेता थे जिन्होंने अपने मत और विचारों से अनेक पीढ़ियों को प्रभावित किया उनका राष्ट्रवाद स्वामी विवेकानंद की भांति पुनुरूत्थान वादी था वह चाहते थे कि भारत एक शक्ति शाली राष्ट्र के रूप में संगठित हो,एक हो और एक प्रचंड एकीकृत और केंद्रीय शक्ति के रूप में एक ही धारा में बहे।

तिलक जी कहते थे जीतने से ज्यादा जरूरी है लड़ना,एक कायर व्यक्ति के लड़ने पर भी जीत संभव है लेकिन असली जीत तब है जब हार निश्चित होने के बावजूद भी लड़ा जाये।

तिलक के लिये स्वराज्य का अर्थ केवल राजनीतिक अर्थ अर्थात स्वशासन ही नहीं था बल्कि इसका नैतिक अर्थ भी था अर्थात आत्मनियंत्रण और आंतरिक स्वतंत्रता उन्होंने स्वराज का वर्णन इन शब्दों में किया है 'यह स्वयं पर केंद्रित और स्वयं पर निर्भर जीवन है' इस दुनिया में भी और परलोक में भी।

तिलक कहते थे 'आलसी व्यक्तियों के लिए भगवान अवतार नहीं लेते, वह मेहनती व्यक्तियों के लिए ही अवतरित होते हैं, इसलिए कार्य करना आरम्भ करें।'

'मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम बिना उत्सवों के नहीं रह सकते, उत्सव प्रिय होना मानव स्वभाव है। हमारे त्यौहार होने ही चाहिए।'

'आप मुश्किल समय में खतरों और असफलताओं के डर से बचने का प्रयास मत कीजिये। वे तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आयेंगे ही।'

स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि मुझे अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाहन करना है।।

ऐसे महामना को पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन राष्ट्र के उत्थान हेतु समर्पित उनका सम्पूर्ण जीवन हम सभी के मन में 'राष्ट्र प्रथम' की भावना का सदैव संचार करता रहेगा।

वक्रोक्ति

हंगामा है क्यों बरपा..शादी ही तो की है!!

संजीव शर्मा

उस्ताद गुलाम अली की यह एक लोकप्रिय ग़ज़ल है- 'हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है।' अकबर इलाहाबादी की लिखी इस ग़ज़ल का मतलब है- ' जरा सी बात पर बेवजह शोर क्यों मचा है, क्यों हंगामा कर रहे हैं।' इस ग़ज़ल का उल्लेख इसलिए क्योंकि कुछ इसी तरह के हंगामे की स्थिति देश के सोशल मीडिया और मीडिया की 'वायरल प्रवृत्ति' ने हिमाचल प्रदेश में हुई एक शादी को लेकर बना रखी है। उनके लिए यह शादी किसी अजूबे से कम नहीं है और जब विषय वायरल होने का माद्दा रखता हो तो फिर सोशल मीडिया के वीर कैसे पीछे रह सकते हैं।

दरअसल,हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय के दो भाइयों द्वारा एक ही लड़की के साथ विवाह करने के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि देश तो देश, विदेशी मीडिया हाउस भी इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे। सामान्य रूप से सामाजिक परंपराओं के लिहाज से यह विवाह अलग और अनूठा भी है लेकिन उस क्षेत्र और समुदाय के लिए सामान्य बात है। यही वजह है कि जब मीडिया ने उस गांव या समुदाय के लोगों से इस विवाह पर प्रतिक्रिया मांगी तो अधिकतर का यही उत्तर था कि इसमें नई बात क्या है? इनका कहना गलत भी नहीं है क्योंकि उस समुदाय और उस क्षेत्र के लिए यह वर्षों पुरानी सामान्य परंपरा है। वैसे तो यह वाकया हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के शिलाई इलाके का था लेकिन सिरमौर क्या, किन्नौर और लाहौल-स्पीति सहित कई जिलों में विभिन्न समुदायों में बहुपति या बहु पत्नी जैसी प्रथाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं।

यदि हम देश के तमाम राज्यों में खासतौर पर आदिवासी और पारंपरिक संस्कारों के पोषक समाज में प्रचलित संस्कृतियों को देखें तो आज उन्हें जानकार हमें अचरज ही होगा मसलन मध्यप्रदेश में भील आदिवासियों में दूल्हे को ससुराल में रखने वाली घर जंवाई प्रथा, अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की नाता प्रथा, विवाह पूर्व यौन संबंध वाली लामसेना प्रथा जैसी तमाम परंपराएं प्रचलित हैं। वहीं, इसी प्रदेश के झाबुआ जिले का भगोरिया मेला युवक युवतियों के जीवन साथी चुनने की आजादी के लिए विख्यात है। मणिपुर में मैतेई समाज में लुंहोंगबा प्रथा आज भी चलन में है इसमें लड़का अपनी पसंद की लड़की को समाज और परिवार की स्वीकृति से भगाकर ले जाता है और फिर उनकी सहमति के आधार पर परिवार उनकी शादी कर देता है। वहीं,ढूकु विवाह प्रथा में लड़का लड़की आज के लिव इन की तरह साथ रहने लगते हैं, बाद में समाज कुछ जुर्माना लगाकर उनके विवाह को स्वीकृति देता है।

जहां तक बहुपति (Polyandry) प्रथा का प्रश्न है तो विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तराखंड के कुछ समुदायों, दक्षिण भारत के नीलगिरी के टोडा आदिवादियों और त्रावनकोर के नांजनाद समाज में,केरल के नायर और थियास समाज में यह परंपरा प्रचलित रही है। मुस्लिम समाज में बहु पत्नी (polygamy) प्रथा तो सामान्य बात है।

अब बात हिमाचल प्रदेश के उस बहुचर्चित विवाह और वहां की परंपराओं की, तो बहुपति प्रथा यहां सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सामान्य बात है। ताजा मामला सिरमौर जिले के हाटी समुदाय का है। हाटी समुदाय अपनी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि बहुपति प्रथा का सबसे उल्लेखनीय प्रसंग महाभारत में है जिसमें द्रौपदी का विवाह पांच पांडव भाइयों से हुआ था। हाटी समुदाय में भी बहु पति प्रथा को जोड़ीदारां या द्रौपदी प्रथा जैसे विभिन्न नामों से नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह प्रथा पांडवों की परंपरा से ही प्रेरित है। उल्लेखनीय बात यह है कि

हाटी समुदाय में बहुपति प्रथा मुख्य रूप से भाइयों के बीच सामूहिक विवाह की प्रणाली है, जहां एक महिला कई भाइयों (आमतौर पर सगे भाइयों) की साझा पत्नी होती है।

हाटी समुदाय में बहुपति प्रथा के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारक हैं मसलन पहाड़ी भूभाग और सीमित उपजाऊ भूमि के कारण परिवारों के लिए संपत्ति का बंटवारा चुनौतीपूर्ण है। बहुपति प्रथा के माध्यम से, परिवार की संपत्ति और भूमि एक इकाई के रूप में बनी रहती है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

इसी तरह, इस प्रथा से भाइयों के बीच एकता और सहयोग बना रहता है। परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक साथ मिलकर खेती, पशुपालन, और अन्य आर्थिक गतिविधियों में योगदान देते हैं। हाटी समुदाय के लोगों का कहना है कि यह प्रथा परिवार और समुदाय की संरचना को मजबूत करती है। हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकार और हाटी समुदाय के प्रवक्ता रमेश सिंगटा बताते हैं कि हमारे समुदाय में बहुपति प्रथा में एक महिला का विवाह एक परिवार के सभी भाइयों से होता है, चाहे उनकी संख्या दो हो या अधिक। विवाह के बाद, पत्नी परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। बच्चों को सभी भाइयों की साझा संतान माना जाता है, और सबसे बड़े भाई को सामान्यतः पिता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रथा में पत्नी को परिवार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है, और वह घरेलू निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रथा में कुछ नियम और परंपराएं भी हैं, जैसे कि भाइयों के बीच समय का बंटवारा और पारस्परिक सहमति। जो यह सुनिश्चित करता है कि परिवार में सामंजस्य बना रहे।

हाटी समुदाय की अनुमानित जनसंख्या लगभग 2 लाख है जो हिमाचल के सैकड़ों गांवों और करीब डेढ़ सौ से ज्यादा पंचायतों में फैली है। यहां तकरीबन हर गांव और परिवार में बहुपति प्रथा के तहत विवाह हुआ है और वे पीढ़ियों से मिल जुलकर सहज भाव से रह रहे हैं। हाल में सिरमौर जिले में दो भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी द्वारा सुनीता नामक युवती से धूमधाम से किए गए विवाह ने भले ही बहुपति प्रथा को पुनः चर्चा में ला दिया है लेकिन इससे उलट हकीकत यह है कि आधुनिकता, शिक्षा, और शहरीकरण के प्रभाव से हाटी समुदाय में भी बहुपति प्रथा धीरे-धीरे कम हो रही है।

युवा पीढ़ी, विशेष रूप से शिक्षित युवा, इस प्रथा को अपनाने में कम रुचि दिखा रहे हैं। इसका कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकल विवाह की अवधारणा के साथ साथ नई पीढ़ी की खेती के अलावा अन्य पेशों में रुचि बढ़ना भी है। इससे संपत्ति के बंटवारे की आवश्यकता भी कम हो रही है।

हाटी समुदाय की बहुपति प्रथा हालांकि सामुदायिक एकता और संसाधनों के संरक्षण पर आधारित है लेकिन यह प्रथा आधुनिक समाज में कई सामाजिक और कानूनी सवाल भी उठाती है, विशेष रूप से लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह प्रथा महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करती है, जबकि समुदाय के भीतर इसे एक सहमति-आधारित व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। वैसे इस प्रथा को समझने के लिए हमें इसे केवल आधुनिक और कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी देखना होगा तभी हम इसके सभी पहलुओं को समझ सकते हैं।

घड़ियाल संरक्षण के पचास साल : क्या हम सफल हुए?

घड़ियाल, अपनी पतली लंबी थूथन और मछलियों पर निर्भरता के कारण नदी पारिस्थितिकी का एक अनूठा जीव है। 20वीं सदी के आरंभ तक यह प्रजाति सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और इरावदी जैसे विशाल नदी तंत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती थी। लेकिन 1940 के दशक में इसकी संख्या मात्र 5-10 हज़ार के बीच रह गई और 1970 के दशक तक यह 98 फीसदी से अधिक क्षेत्र से गायब हो चुकी थी। इसी संकट को देखते हुए, 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से क्रोकोडाइल कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश की तीन दुर्लभ घड़ियाल (मगरमच्छ) प्रजातियों, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ को संरक्षित करना था। यह परियोजना 'पालन और पुनः प्रक्षेपण' विधि का उपयोग करके, बंदी अवस्था में मगरमच्छों को पालने और फिर उन्हें प्राकृतिक आवासों में छोड़ने पर केंद्रित थी। इसके अंतर्गत देश भर में 16 मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र और 11 मगरमच्छ अभयारण्यों की स्थापना की गई। इनमें नेशनल चंबल सैंक्चुरी, कटर्नियाघाट, सतकोसिया, सोन घड़ियाल अभयारण्य और केन घड़ियाल अभयारण्य मुख्य है।

पर्यावरण

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

18 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस पर मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की स्वर्ण जयंती मनाई गई। भारत सरकार ने 1975 में जब घड़ियालों के संरक्षण के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तब यह उम्मीद थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सरकारी संसाधनों के साथ यह मछलीभक्षी मगरमच्छ– जिसे वैज्ञानिक भाषा में गैवियालिस गैंजेटिकस कहा जाता है – फिर से भारतीय नदियों में आबाद हो सकेगा। लेकिन आज, इस प्रयास के 50 साल बाद, हमें खुद से यह कठिन सवाल पूछना होगा- क्या हम वाकई घड़ियाल को बचा पाए हैं?

जब घड़ियाल की बात होती है, तो अक्सर उसे एक विलुप्तप्राय जलचर के रूप में देखते हैं - एक ऐसा जीव, जो अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन घड़ियाल सिर्फ एक प्रजाति का नाम नहीं है। उसकी उपस्थिति खुद में एक संकेत है, नदी की सेहत, पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता के प्रति हमारी संवेदनशीलता का।

घड़ियाल, अपनी पतली लंबी थूथन और मछलियों पर निर्भरता के कारण नदी पारिस्थितिकी का एक अनूठा जीव है। 20वीं सदी के आरंभ तक यह प्रजाति सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और इरावदी जैसे विशाल नदी तंत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती थी। लेकिन 1940 के दशक में इसकी संख्या मात्र 5-10 हज़ार के बीच रह गई और 1970 के दशक तक यह 98 फीसदी से अधिक क्षेत्र से गायब हो चुकी थी।

इसी संकट को देखते हुए, 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (NDP) के सहयोग से क्रोकोडाइल कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश की तीन दुर्लभ घड़ियाल (मगरमच्छ) प्रजातियों, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ को संरक्षित करना था। यह परियोजना 'पालन और पुनःप्रक्षेपण' विधि का उपयोग करके, बंदी अवस्था में मगरमच्छों को पालने और फिर उन्हें प्राकृतिक आवासों में छोड़ने पर केंद्रित थी। इसके अंतर्गत देश भर में 16 मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र और 11 मगरमच्छ अभयारण्यों की स्थापना की गई। इनमें नेशनल चंबल सैंक्चुरी, कटर्नियाघाट, सतकोसिया, सोन घड़ियाल अभयारण्य और केन घड़ियाल अभयारण्य मुख्य है।

हाल की वार्षिक गणनाओं के अनुसार, आज भारत में वयस्क घड़ियालों की संख्या मात्र 650 के आसपास है, जिनमें से 550 नेशनल चंबल सैंक्चुरी में ही सीमित हैं। सवाल उठता है कि आधी सदी चले इस विशाल संरक्षण कार्यक्रम का परिणाम इतना सीमित क्यों है?

इसका जवाब संरक्षण की मूल रणनीति में निहित है – हमने बार-बार बंदी प्रजनन और पुनः प्रक्षेपण पर बल दिया, लेकिन उनकी प्राकृतिक निवास – नदियां – निरंतर संकट में रहीं।

घड़ियाल की मौजूदगी यह भी दर्शाती है कि वह नदी अब भी जीवित है, उसमें प्रदूषण नहीं फैला है, उसमें प्रवाह बचा है, और उसमें जीवन पल रहा है। इसलिए वैज्ञानिक घड़ियाल को एक 'जैव संकेतक' मानते हैं - एक ऐसा जीव जो हमें बिना कुछ कहे यह बता देता है कि नदी कितनी स्वस्थ है।

घड़ियालों के जीवित रहने का पूरा दारोमदार नदियों पर है। वे खुले, बहावयुक्त नदी प्रवाह, रेत के टीलों और मछलियों की पर्याप्त उपलब्धता वाले वातावरण में ही पनप

सकते हैं। लेकिन इन पांच दशकों में भारतीय नदियां बेतहाशा रेत खनन, बांधों, बैराजों, प्रदूषण और अवैध मछली पकड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, चंबल जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक और अवैध रेत खनन ने घड़ियालों के घोंसले बनने वाली रेत पट्टियों को नष्ट कर दिया है। कई क्षेत्रों में तो घोंसले लगभग समाप्त हो चुके हैं। घड़ियालों की 90 फीसदी से अधिक मौतें मानसून के बाद पहले तीन महीनों में होती हैं – यह दिखाता है कि केवल अंडे देना और बच्चे निकलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका जीवित रहना ही असली चुनौती है। घड़ियाल का संरक्षण अपने आप में रेत खनन पर नियंत्रण की मांग को जन्म देता है, जो बाढ़ नियंत्रण से लेकर जलप्रवाह की गुणवत्ता तक, कई प्राकृतिक संतुलनों को बनाए रखने में सहायक होता है।

मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट द्वारा 2008 में शुरू किए गए घड़ियाल इकॉलॉजी प्रोजेक्ट के प्रमुख अन्वेषक प्रो. जेफरी लैंग के अनुसार 'अब ज़रूरत है कि हम नदी पारिस्थितिकी की संपूर्णता पर ध्यान दें। घड़ियाल संरक्षण के प्रयास तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक कि नदियां अपने प्राकृतिक रूप में मुक्त बहने वाली न हों, उनमें बांध/बैराज न्यूनतम हों और रेत खनन नियंत्रित हो।'

इसी तरह, नेचर कंज़र्वेशन सोसाइटी के सचिव राजीव चौहान कहते हैं, 'बंदी प्रजनन और पुनर्वास केवल एक 'बैंड-ऐड' उपाय है। जब तक हम प्रवाह, मत्स्य पालन और रेत खनन पर सख्त नियंत्रण नहीं रखते, तब तक मगरमच्छों के पुनर्वास के प्रयास व्यर्थ है।'

ओडिशा ही एकमात्र राज्य है, जहां तीनों मगरमच्छ प्रजातियां - खारे पानी के मगर (भितरकनिका), घड़ियाल (सतकोसिया) और मगरी (सिमलीपाल) - पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भितरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। दोनों क्षेत्र भारत में खारे पानी के मगरमच्छों के तीन गढ़ों में से हैं; तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। वर्ष 2025 की जनगणना में 1826 खारे पानी के मगर, 16 घड़ियाल और लगभग 300 मगरी गिने गए। हालांकि यह संरक्षण की सफलता दर्शाता है, लेकिन हाल ही में भितरकनिका और उसके आसपास के इलाकों में इंसानों और मगरमच्छों के बीच संघर्ष बहुत बढ़ गया है। पिछले साल जून और अगस्त के बीच पार्क और उसके आसपास मगरमच्छों के हमलों में एक 10 वर्षीय लड़के सहित छह लोगों की मौत हो गई थी। वहां अब इन इलाकों में बाड़बंदी और चेतावनी प्रणाली जैसे उपाय लागू किए जा रहे हैं।

एक ताज़ा अध्ययन में पाया गया है कि आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन से घड़ियालों के लिए उपयुक्त क्षेत्र 36 फीसदी से 145 फीसदी तक बढ़ सकता है - विशेषतः उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, असम, उत्तराखंड जैसे राज्यों में। वहीं ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य शायद अपनी उपयुक्तता खो बैठेंगे।

अध्ययनकर्ताओं ने सिफारिश की है कि ब्रह्मपुत्र और महानदी घाटियों में संभावित क्षेत्रों का मैदानी सर्वेक्षण किया जाए, उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, और स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाए।

घड़ियाल संरक्षण के 50 वर्षों का अनुभव हमें यही सिखाता है कि सिर्फ प्रजाति पर केंद्रित नीतियां नाकाफी है। जब तक हम नदियों को, उनके प्रवाह को, उनकी जैव विविधता को, उनके किनारे के समुदायों को संरक्षण नीति का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक घड़ियाल जैसे जीव केवल सरकारी आंकड़ों में ही जीवित रहेंगे। (स्रोत फीचर्स)

मोबाइल चोरी एवं फोन-पे एप से राशि ट्रांसफर करने वाले आरोपी पकड़ाए

बैतूल। सारणी पुलिस ने मोबाइल चोरी करने और फोन-पे एप से राशि ट्रांसफर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 17 जुलाई को राकेश बाबरिया पिता गंगाराम बाबरिया निवासी आज़ाद नगर पाथाखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि के समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके निवास स्थान से मोबाइल फोन चोरी कर लिया और उक्त मोबाइल का उपयोग कर फोन-पे एप के माध्यम से 40,000 की राशि ट्रांसफर कर ली। शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305 बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। अनुसंधान के दौरान संदेही अंकित बेले से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें उसने उक्त चोरी की घटना को अपने सहयोगियों विशाल बेले एवं निक्की के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया। आरोपितों ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल में फोन-पे का लॉक एक्टिव नहीं था, जिससे उन्होंने राशि का ग़लत उपयोग करते हुए पहले निक्की के खाते में और उक्त राशि को तत्पश्चात अंकित बेले के खाते में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस द्वारा आरोपी अंकित बेले से 15,000 तथा विशाल बेले से 25,000 कुल 40,000 की नकद राशि बरामद की गई है। तीसरा आरोपी निक्की वर्तमान में फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्रवाही में उप निरीक्षक वंशज श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक ज्ञान सिंह टेकाम, प्रधान आरक्षक मनोज डेहरिया, आरक्षक सुभाष मण्डलोई और आरक्षक रवि दर्शिमा की सराहनीय भूमिका रही।

छात्रों का तिलक मिटाने, कलावा डस्टबिन में फेंकने का आरोप

एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

बैतूल। बैतूल के एक निजी स्कूल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने जमकर हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। कार्यकर्ताओं को रोकने पर परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल गुरुवार सुबह 11 बजे एबीवीपी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप था कि स्कूल में बच्चों को तिलक लगाने और कलावा बांधने की मनाही है। ऐसा करने पर तिलक मिटाने के साथ ही कलावा कटवाकर डस्टबिन में

फेंकने का काम कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन इन आरोपों को नकार रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ता स्कूल प्रिंसिपल को बुलाने पर अड़े थे। प्रदर्शन करीब 4.30 घंटे चला। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीओपी सुनील लाटा और टीआई सविंद धुर्वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तिलक लगाकर आने और कलावा बांधने पर मनाही से छात्रों की धार्मिक आस्था से जुड़ी परंपराओं पर रोक लगाना गलत है। प्रिंसिपल सिस्टर जोजिना ने स्कूल गेट पर आकर कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा कि स्कूल में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। इस पर कार्यकर्ताओं ने इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करने की मांग की। जिस पर स्कूल शिक्षा विभाग के योजना अधिकारी ने मंच से घोषणा की कि स्कूल में किसी भी धर्म, जाति, रीति-रिवाज को न मानने जैसी कोई रोक नहीं है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन खत्म किया।

भाजपा 10 से 14 तक निकलेगी तिरंगा यात्रा

आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिला टोली का गठन

बैतूल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मार्गदर्शन में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा एवं पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम हेतु जिला टोलीयों का गठन किया गया है। संभागीय संगठन प्रभारी पंकज जोशी जी एवं जिला संगठन प्रभारी सुजीत जैन की सहमति से भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार ने तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के लिए जिला संयोजक कमलेश सिंह एवं जिला सह संयोजकद्वय भास्कर मगरदे ,ममता मालवी को मनोनीत किया है। इसी प्रकार कुशाभाऊ ठाकरे जयंती, अटलजी की पुण्यतिथि कार्यक्रम हेतु जिला संयोजक कृष्णा गायकी व सह संयोजक द्वय देवीसिंह ठाकुर, इंद्रपाल पुण्डे को मनोनीत किया गया है।

अब तक सिर्फ 60 प्रतिशत कचरा हटा पाई कंपनी, निर्धारित समय से 5 माह अतिरिक्त गुजरे

ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे की प्रोसेसिंग का काम बंद, दुर्गंध से लोग परेशान

बैतूल। शहर के वार्डो का कचरा गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में एकत्रित किया जाता है, जहां कचरे की प्रोसेडिंग का ठेका दिया है, लेकिन अभी कचरे की प्रोसेसिंग का कार्य बंद है। जिससे कचरा नष्ट करने के काम में देरी हो रही है और यह कचरा लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगातार कचरा एकत्रित होने से कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे है। बता दे कि नगरपालिका शहर के 33 वार्डो से रोजाना डोर-टू-डोर और सार्वजनिक स्थानों, मार्केट से कचरा कलेक्ट करती है। यह कचरा गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है। जहां कचरे की प्रोसेसिंग की जाती है। नगरपालिका ने इसका ठेका ईकोस्टन कंपनी नोएडा को दिया है। कंपनी द्वारा जमीन में 10 से 15 फीट गहरी खुदाई कर कचरा बाहर निकालकर टीले बना दिए हैं, लेकिन इसे अलग- अलग करने का काम मशीनें थमने के कारण रुक गया है। बताया जा रहा है कि बारिश आने से पूरा कचरा गीला हो गया और कचरे के बीच में पानी थम गया है। अब इस पानी के सूखने की राह देखनी पड़ रही है। यहां पर जमीन में से खोदकर निकाला कचरा भीगने से कीचड़ होने पर बदबू और मक्खियों का अंबार लग रहा है। जिससे आसपास के लोग परेशान हैं।

6 माह की टाइम लिमिट, बीत गये 11 महीने- नगरपालिका ने लेगेसी वेस्ट के प्रोजेक्ट का ठेका ईकोस्टन कंपनी नोएडा को देते हुए अगस्त 2024 में वर्क ऑर्डर जारी किया था। इस प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट 6 माह थी। फरवरी 2025 तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन टाइम लिमिट से 5 महीने अधिक होने पर भी केवल 60 प्रतिशत कचरा ही हट पाया है। इधर नपा ने अब तक कंपनी पर कोई पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई नहीं की है। जबकि 10 प्रतिशत पेनाल्टी हर बिल पर लगनी चाहिए। बारिश में यह गीला कचरा बीमारियों का सबब बनता जा रहा है। अब काम बारिश बाद ही पूरे होने की उम्मीद है।

प्रतिदिन निकलता है सैकड़ों टन कचरा- नगरपालिका द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहित किया जाता है। एक अनुमान से शहर के 33 वार्डों से लगभग प्रतिदिन 30 से 40 टन कचरा निकल जाता है और इस कचरे को शहर के समीप स्थित गौठाना के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा किया जाता है। पहले आसपास ज्यादा मकान नहीं थे, लेकिन अब आबादी बढ़ने के साथ-साथ मकानों का भी निर्माण हो गया है। ऐसे में हवा चलने पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा उड़कर घरों तक पहुंच जाता है और लोगों को गंदगी के साथ-साथ दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है। रहवासी बताते है कि कचरे की दुर्गंध के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी आती है। कचरे के कारण मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है।

60 प्रतिशत ही हट पाया कचरा

गौठाना स्थित नगरपालिका का ट्रेंचिंग ग्राउंड करीब 8 एकड़ पर फैला हुआ है। यहां कचरा अलग-अलग करने और नष्ट करने के लिए दो मशीनें कंपनी ने लगाई हैं। इनकी क्षमता 300-300 टन प्रतिदिन की है। इन मशीनों तक कचरा पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट लगे हैं। नोएडा की कंपनी को ठेका देने और वर्क ऑर्डर होने के बाद अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस प्रक्रिया में अगस्त 2024 से लेकर जनवरी तक का समय लग गया। जनवरी 2025 में कंपनी ने काम शुरू किया। पांच महीने की देरी से काम शुरू होने के कारण 60 प्रतिशत ही कचरा हट पाया। इसके बाद बारिश आने पर कचरा गीला हो गया और मशीनों को बंद करना पड़ा।

कचरे की दुर्गंध से परेशान लोग

शहर के गौठाना स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लाखों टन कचरा जमा है। यहां अभी भी शहर का कचरा एकत्रित किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्ट करने के बाद इसे, इसी ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। जिससे यहां कचरे की मात्रा बढ़ते ही जा रही है। लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी नगरपालिका की लापरवाही साफ झलक रही है। लापरवाही यह भी है कि कचरे की प्रोसेसिंग के दौरान कचरे से दुर्गंध या हानिकारक गैस न निकले, इसके लिए नपा द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये है। इस इलाके में हर तरफ कचरा ही नजर आता है। कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं और लोगों को दुर्गंध सहित गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।

इनका कहना है -

बारिश का पानी लगने से कचरे का वेट बढ़ गया है। जिसके कारण फिलहाल प्रोसेसिंग का काम रोक दिया है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, जल्द से जल्द कचरे की प्रोसेसिंग कराने का प्रयास करेंगे। यदि दुर्गंध की समस्या है तो नपा स्वच्छता प्रभारी से कहकर ब्लीचिंग पाउडर का छिडक़ाव करवाया जायेगा, ताकि कचरे से दुर्गंध न उठे।

- पंकज धुर्वे,
सब इंजीनियर, नगरपालिका बैतूल

आज का विद्युत कटौती शेड्यूल

बैतूल। बिजली कंपनी द्वारा 1 अगस्त को गंज फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। मेंटेनेंस कार्य के चलते शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक 11 केव्ही गंज फीडर के आबकारी, सिंधी कॉलोनी, देना बैंक, लोहिया वार्ड, तेल टंकी, लक्की सेंटर, कांति शिवा टॉकीज, सेंट्रल बैंक, एसबीआई बैंक, मैकेनिक चौक, अग्रवाल पेट्रोल पंप, बीजेपी कार्यालय, डॉ मूले गुरुद्वारा रोड हाथी नाला, डॉ लश्करे, बीएसएनएल ऑफिस, पुलिस क्वार्टर, हाउसिंग बोर्ड गंज, महाराष्ट्र बैंक आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल शहर जोन-1 के प्रबंधक ने बताया कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

ठेकेदार ने काम करवाकर 16 मजदूरों की नहीं दी मजदूरी

श्रमिकों ने भौंरा पुलिस चौकी में की शिकायत

बैतूल / भौंरा। शाहपुर तहसील के ग्राम पंचायत सालीमेट अंतर्गत ग्राम सेमलपुरा के 16 ग्रामीण मजदूरों ने ठेकेदार सुनील त्यागी और सुपरवाइजर हरि के खिलाफ भोपाल में काम कराकर मजदूरी नहीं देने की शिकायत पुलिस चौकी भौंरा में दर्ज कराई है। मजदूरों का कहना है कि उनसे भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में काम कराया गया और अब उनकी 44,500 की मेहनताना राशि नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वे 4 जून 2025 से

भोपाल में निर्माण कार्य में लगे थे। उन्हें 500 प्रतिदिन की मजदूरी पर काम पर रखा गया था। मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी सुपरवाइजर हरि की थी। शुरुआत में 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बार-बार मांगने के बाद भी सिर्फ कुछ लोगों को आंशिक रूप से एडवांस दिया गया और शेष राशि रोक दी गई। किसी को 1000 मिले, किसी को 3000, लेकिन अधिकांश का 2500 से 4000 तक भुगतान बकाया है। इनमें पुरुष और महिला दोनों मजदूर शामिल हैं। बताया गया कि भोपाल में ही रुके 10 मजदूरों को 19 जुलाई 2025 को श्रम कार्यालय भोपाल में सहायक श्रम आयुक्त पी. जेसमीन अली सितारा के हस्तक्षेप से आंशिक भुगतान दिलवाया गया था। लेकिन 16 मजदूर, जो बोवनी के लिए गांव लौट आए थे, उन्हें आज तक पूरा भुगतान नहीं मिला।

मजदूरों ने बताया, पहले ही दी थी जानकारी

मजदूरों ने कहा कि उनसे सिर्फ एक माह काम की बात हुई थी। जब बोवनी का समय आया तो उन्होंने हफ्ते भर पहले ही सुपरवाइजर और ठेकेदार को गांव लौटने की जानकारी दी थी। इसके बावजूद अब उन पर बिना बताए काम छोडऩे का आरोप लगाकर भुगतान से इनकार किया जा रहा है। मजदूर बाजुलाल, मजदूर सेमलपुरा ने बताया हम भोपाल जाकर मेहनत से काम किए। ठेकेदार ने कहा था हर 15 दिन में मजदूरी देंगे, लेकिन अब टाल-मटोल कर रहा है। खेत में बोवनी करनी थी, इसलिए लौट आए, अब पैसे भी नहीं दे रहा। पुलिस से उम्मीद है कि हमें हमारा हक दिलवाएगी। मुन्नीबाई, मजदूर सेमलपुरा ने कहा घर के हालात खराब हैं। बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। हमने पसीना बहाकर काम किया है, लेकिन आज तक पूरी मजदूरी नहीं मिली। हम चाहते हैं कि शासन हमें न्याय दे और मजदूरी दिलवाए।

पुलिस और सुपरवाइजर का पक्ष

भौंरा पुलिस चौकी प्रभारी नीरज खरे ने बताया मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे। मजदूरों की शिकायत पर ठेकेदार को फोन लगाया गया, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। वहीं सुपरवाइजर हरि ने कहा मैं केवल मजदूरों की देखरेख करता हूं, भुगतान का कार्य ठेकेदार करता है। वह अभी यहां नहीं है। मजदूर अपनी मर्जी से यहां से गए थे, उन्हें पेमेंट लेकर ही जाना था। मजदूरों ने ठेकेदार सुनील त्यागी और सुपरवाइजर हरि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने भौंरा पुलिस चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय और तत्काल बकाया राशि दिलवाने की अपील की है।

कपड़ा दुकान में फिर चोरी, नकदी और दस्तावेज गायब

बैतूल। कोठी बाजार क्षेत्र की प्रतिष्ठित कपड़ा दुकान अरिहंत में बुधवार रात चोरी हो गई। चोरों ने दुकान का गेट तोडक़र प्रवेश किया और नकदी सहित जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। इसी दुकान में दो माह पूर्व 21 मई को 10 लाख 20 हजार की चोरी हुई थी। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दुकान संचालक पदम सुराणा ने कोठी बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई की रात वे 8.30 बजे दुकान बंद कर घर गए थे। गुरूवार सुबह 9.30 बजे जब दुकान पहुंचे तो मुख्य गेट टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो गल्ले से 12 हजार रुपए

नकद और एक पर्स गायब था। पर्स में एसबीआई का एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और लगभग 3 हजार रुपए की चिल्लर थी। इस बार चोर दुकान के पिछले हिस्से से घुसे। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस इनके आधार पर जांच कर रही है। लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार हो रही वारदातों से व्यापारियों में आक्रोश है। बढ़ती चोरी की घटनाओं से व्यापारी और आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे ठोस सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं।

छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को 8 माह से नहीं मिला वेतन

अजाक्स ने सौंपा ज्ञापन ,सहायक आयुक्त ने दिया आश्वासन

बैतूल। जिले के छात्रावासों में कार्यरत सैकड़ों अंशकालीन कर्मचारियों को पिछले 6 से 7 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) बैतूल द्वारा सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग विवेक कुमार पांडे को सैकड़ों कर्मचारियों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए संघ के सदस्यों ने सहायक आयुक्त का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन भी किया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मई-जून माह में अंशकालीन कर्मचारियों ने छात्रावासों में नियमित रूप से सेवाएं दी हैं, जिनकी उपस्थिति वेतन पत्रक में अंकित कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजी गई। इसके बावजूद अनुसूचित जाति के छात्रावासों में कार्यरत इन कर्मचारियों को विगत आठ माह से नियमित वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर सहायक आयुक्त विवेक

कुमार पांडे ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि जैसे ही बजट प्राप्त होगा, वेतन का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ग्राम हरदू, विकासखंड चिचोली में विभागीय मंत्री के प्रवास के दौरान यह घोषणा की गई थी कि अंशकालीन कर्मचारियों के वेतन में शीघ्र वृद्धि की जाएगी तथा शासन स्तर पर इस दिशा में प्रयास जारी हैं। यह बात उन्होंने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में दोहराई। कर्मचारियों के हित में लगातार लड़ाई लड़ रहे जिला अध्यक्ष एवं अजाक्स पदाधिकारियों की सराहना करते हुए अजाक्स प्रांतीय अध्यक्ष माननीय चौधरी मुकेश मौर्य, स्टेट संगठन समीक्षक एवं प्रदेश अध्यक्ष पेंशन एसोसिएशन माननीय रामकिशोर दाहिया, मुख्य स्टेट समन्वयक माननीय श्यामलाल डोहरिया ने इस कार्य को सराहनीय बताते हुए जनहित में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए इसी तरह कार्य करते रहने की प्रेरणा दी है।

बैतूल ने योजनाओं के क्रियान्वयन में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

15 विभागों की 37 सेवाओं में प्रदेश में जिला बना अग्रणी

कलेक्टर के सतत मार्गदर्शन में की जा रही मॉनिटरिंग

बैतूल। मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड केपिआई के अंतर्गत चयनित 15 विभागों की 37 सेवाओं में बैतूल जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपना प्रथम स्थान बनाया है। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी की सतत मॉनिटरिंग और विभागीय समन्वय का परिणाम रहा कि जिला प्रदेश के सभी जिलों में अग्रणी बना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती एवं डायवर्सन जैसे प्रकरणों में बेहतर निराकरण किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने हर घर जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति में प्रभावी प्रगति की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के प्रकरणों को प्राथमिकता से हल किया। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने लोन से संबंधित मामलों का त्वरित समाधान किया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण किया गया, जिससे कृषकों को समय पर लाभ मिल सका।

6 हजार 276 शिकायत दर्ज- प्राप्त जानकारी के अनुसार जून महीने में सीएम हेल्पलाइन पर कुल 6 हजार 276 शिकायतें दर्ज की गई थी। प्राप्त शिकायतों में संतुष्टि के साथ बंद की गई शिकायत 50.39 प्रतिशत, 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतें 13.13 प्रतिशत, निम्न गुणवत्ता से बंद की गई शिकायतें 9.87 प्रतिशत तथा नोट अटेंडेंस 9.73 शिकायतों का निराकरण किया है। जिला प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज अधिकांश शिकायतों का शीघ्र समाधान किया और लोगों को संतुष्टि प्रदान की। हालांकि कुछ शिकायतें 50 दिनों से अधिक समय तक लंबित रही, जिन्हें निराकरण के लिए और प्रयास किए जाएंगे।

इन विभागों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, खनिज साधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वित्त विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास एंव आवास विभाग, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत निराकरण कर ए ग्रेडिंग दर्ज की है। बैतूल जिला विगत छह माह से निरंतर ए ग्रेडिंग प्राप्त कर रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निराकरण में निरंतर उच्च प्रदर्शन ने बैतूल को प्रदेश में एक आदर्श जिला बना दिया है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा प्रत्येक शिकायत के निराकरण के बाद संतुष्टि स्तर का मूल्यांकन भी किया जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी शिकायत बिना समाधान के न रह सके।

जिले को मिले दो शव वाहन, हरी झंडी दिखाकर किया औपचारिक शुभारंभ

बैतूल। विधायक प्रतिनिधि स्वास्थ्य विभाग डॉ. अशोक बारंगा एवं अपर कलेक्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. जगदीश घोरे एवं जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र राजपूत द्वारा गुरूवार को जिला चिकित्सालय परिसर से दो शव वाहनों को हरी झंड़ी दिखाकर औपचारिक शुभारंभ किया गया।

सीएमएचओ डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय अस्पतालों में रोगी अथवा दुर्घटना पीड़ित के उपचार के दौरान मृत्यु उपरांत मृतक को निवास स्थल/श्मशान घाट तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से शव वाहन सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। शव वाहन का संचालन जिले की सीमा के अंदर किया जाएगा, शव वाहन शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में हुई मृत्यु के प्रकरणों में ही उपयोग किए जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

होली चौक के पास पुरानी और जर्जर दीवार गिराई

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत पुराने व जर्जर भवनों को गिराने के निर्देश दिये है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रशासन द्वारा आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत हरदा के होली चौक के पास पुरानी और जर्जर हो चुकी दीवार गिराई गई। इस दौरान हरदा तहसीलदार श्री राजेंद्र पवार और नगर पालिका सीएमओ श्री कमलेश पाटीदार मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलने से हुकुमचंद के जीवन में आईं खुशियां

रायसेन (निप्र)। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जनजातीय वर्ग के नागरिकों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ सुगमता से पहुंच रहा है। अभियान के तहत जनजातीय बहुल ग्रामों में शिविर लगाकर जनजातीय वर्ग को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम कचनारिया निवासी हितग्राही श्री हुकुमसिंह धरती आबा अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, विद्युत कनेक्शन, सम्बल कार्ड, खाद्यान्न पात्रता पर्ची सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलने से बेहद खुश है और इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। हितग्राही श्री चरण सिंह गोड ने बताया कि पहले वह परिवार के साथ कच्चे घर में निवास करते थे जिसमें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का आवास मिल गया है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्जवला योजना, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, विद्युत कनेक्शन सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

जिला न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया पौधरोपण

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा वृक्षारोपण विशेष अभियान के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर सभी को विधिक सेवा प्रकृति की रक्षा का संकल्प दिलाया गया और अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की कई। न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 15 जुलाई से 15 सितंबर 2025 तक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिला एवं तहसीलों पर जल की उचित व्यवस्था एवं संरक्षित स्थानों पर पीपल, नीम, वट वृक्ष, इमली, बेल, कविट, आंवला, कटहल और आम आदि के पौधे रोपित किए जा रहे हैं और उनका संरक्षण भी किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री वैभव मंडलोई, विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, एनजीओ के प्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्ता अन्य अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री राजेन्द्र कुशवाह, आसिफ खान, श्री अमन कुलश्रेष्ठ, कु.एकता सेन, कु. संयोगिता सोलंकी, न्यायालयीन कर्मचारीगण, विधिक सेवा के कर्मचारीगण व पैरालीगल वालेन्टियर्स ने भी पौधरोपण किया।

एम्स भोपाल की ट्रॉमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन टीम को ईएम-जीएआरवी 2025 में कई सम्मान

भोपाल। एम्स भोपाल, अपने कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में, ट्रॉमा एवं आपातकालीन चिकित्सा विभाग ने एम्स ऋषिकेश द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित आपातकालीन चिकित्सा सम्मेलन ईएम जीएआरवी 2025 में सहभागिता कर संस्थान की शैक्षणिक एवं चिकित्सीय उत्कृष्टता को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। सम्मेलन में विभाग की टीम ने उत्कृष्ट प्रस्तुति देते हुए कई पुरस्कार हासिल किए, जो आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स भोपाल की राष्ट्रीय नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाते हैं। विभाग के शैक्षणिक जूनियर रेजिडेंट्स ने अनुसंधान प्रस्तुतियों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। डॉ. नितिन सिंघल ने पोस्टर प्रेजेंटेशन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया, जबकि डॉ. आकाश ने पोडियम प्रेजेंटेशन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया, जो उनके शोध कौशल और प्रस्तुति क्षमता को रेखांकित करता है। फैकल्टी सदस्यों को भी उनके शैक्षणिक और चिकित्सीय योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। डॉ. पूजा थावरे को कल केस रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता पुरस्कार डॉ. सौरभ त्रिवेदी को आपातकालीन चिकित्सा में उत्कृष्ट फैकल्टी केस रिपोर्ट पुरस्कार और डॉ. रश्मि वर्मा को श्रेष्ठ अनुसंधान पुरस्कार (सिस्टमेटिक रिव्यू श्रेणी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग की फैकल्टी ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न कार्यशालाओं का सफल संचालन करते हुए प्रशिक्षुओं को आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया। डॉ. अंशु प्रियंका लकड़ा ने एयरवे मैनेजमेंट कार्यशाला का निर्देशन किया, डॉ. सौरभ त्रिवेदी ने आपातकालीन चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड-गाइडेड ब्लॉक्स कार्यशाला का नेतृत्व किया, और डॉ. रश्मि वर्मा ने 2डी ईको कार्यशाला के माध्यम से डायग्नोस्टिक कौशल को और सुदृढ़ किया। ट्रॉमा एवं आपातकालीन विभागाध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि ये उपलब्धियां विभाग की अनुसंधान, शिक्षा और क्लीनिकल नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं तथा यह सफलता एम्स भोपाल की राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका को सशक्त बनाती है।

प्रशिक्षणार्थी उप जिलाध्यक्षों ने विधानसभा का भ्रमण किया

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया मार्गदर्शन

भोपाल। आरसीवीपी प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप जिलाध्यक्षों ने गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा का भ्रमण किया और विधानसभा की कार्यवाही देखी। इस अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उप जिलाध्यक्षों से भेंट की और उनका मार्गदर्शन किया।

श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी प्राथमिकता काम का समय पर निराकरण होना चाहिए। उप जिलाध्यक्षों को अपने शुरुआती करियर में चुनौतीपूर्ण और फील्ड के काम को प्राथमिकता देना चाहिए।

श्री तोमर ने कहा कि आप लोगों के पास आम जनता, गरीब, किसान अपनी समस्याओं को ले कर आयेंगे, आप की प्राथमिकता उनका निराकरण होना चाहिए। श्री तोमर ने उप जिलाध्यक्षों से जनता से जुड़ कर और वहां से फीडबैक लेने पर भी बल दिया। उन्होंने अधिक से अधिक अध्ययन पर भी जोर दिया।

प्रदेश में भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, किसानों की बदहाली और जनता के साथ अन्याय हो रहा है : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जनता को गुमराह करने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और कानून-व्यवस्था में पूरी तरह विफल रहने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश दोनों ही असुरक्षा, अव्यवस्था और धोखाधड़ी के दौर से गुजर रहे हैं। श्री पटवारी ने सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया।

राहुल गांधी का संसद में सवाल - राहुल गांधी ने दो दिन पहले संसद में कहा था कि देश की समस्याओं को सामने लाना और सच्चाई बताना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कश्मीर में 26 लोगों की हत्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था- ऐसी सजा देंगे कि जिसने किया, उसने सोचा भी नहीं होगा।

साथ ही, बार-बार दावा किया गया कि भारत, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हर हाल में वापस लेगा।

गृह मंत्री ने भी संसद में कहा था- जान दे देंगे, पर पीओके लेकर रहेंगे। लेकिन श्री पटवारी ने कहा कि हकीकत इससे उलट है। सरकार जनता को गुमराह कर रही है और इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर घोटाला

शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर 5.70 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन पोर्टल क्रैश हो गया। 4,503 शिक्षकों ने आवेदन किया, लेकिन 11,584 तबादले कर दिए गए। नियमों के अनुसार केवल 10 प्रतिशत तबादले संभव थे, लेकिन विभाग ने मनमानी करते हुए 7,976 स्वैच्छिक तबादले किए।

श्री पटवारी ने इसे 'तबादला उद्योग' करार देते हुए कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था की नींव को हिला रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

महिलाओं और दलित-आदिवासी वर्ग पर अत्याचार

1 जनवरी 2024 से 20 जून 2025 तक 10,840 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। औसतन हर दिन 20 बलात्कार और 38 महिलाएं लापता हो रही हैं। महिला अपराधों में 33 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, लेकिन न्याय की दर अत्यंत कम है। दलित और आदिवासी वर्ग पर अत्याचार लगातार जारी हैं, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। श्री पटवारी ने सरकार से सवाल किया कि महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

किसानों के साथ धोखा

श्री पटवारी ने कहा कि कृषि मंडियों में अव्यवस्था और फसल समर्थन मूल्य में धोखाधड़ी लगातार जारी है। सरकार ने गेहूं, लहसुन, प्याज, आलू और सोयाबीन के लिए उचित मूल्य का वादा किया था। हकीकत यह है कि सोयाबीन आज भी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे बिक रहा है, जबकि सरकार ने 6,000 रुपये का वादा किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस उनके घरों के सामने अनशन करेगी।

प्रशासनिक ट्रांसफर फैक्ट्री

377 आईएएस में से 42 और 305 आईपीएस में से 38 अधिकारियों के बार-बार तबादले किए गए। सरकार ने ट्रांसफर को एक 'उद्योग' बना दिया है, जिससे प्रशासनिक कार्य और विकास ठप हो गए हैं।

पटवारी ने कहा केंद्र और राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कर्मचारी परेशान हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था चरम पर है। कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है और हर स्तर पर सरकार की नाकामियों को उजागर करती रहेगी।

एम्स भोपाल में ट्रांसलेशनल डर्मेटोलॉजी की शुरुआत, अब त्वचा रोगों का होगा सटीक इलाज

भोपाल। एम्स भोपाल, अपने कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में शैक्षणिक नवाचार और अनुसंधान उत्कृष्टता के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में, एम्स भोपाल ने त्वचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ट्रांसलेशनल डर्मेटोलॉजी इनिशिएटिव की शुरुआत की है। यह पहल प्रयोगशाला अनुसंधान, क्लीनिकल विज्ञान और डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों को एकीकृत कर व्यक्तिगत और सटीक त्वचा देखभाल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत में सोरायसिस, एक्ज़िमा, विटिलिगो और दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं, जिनका उपचार अब तक सामान्य लक्षणों पर आधारित रहा है। यह नई पहल प्रत्येक व्यक्ति की जैविक और आनुवंशिक संरचना के आधार पर उपचार को अनुकूलित करने का प्रयास करती है। इस पहल के अंतर्गत त्वचा रोग विभाग, ट्रांसलेशनल मेडिसिन विभाग, दुर्लभ रोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जैव रसायन विभाग, प्रिसिशन मेडिसिन सेंटर और इनोवेशन सेंटर मिलकर कार्य कर रहे हैं। प्रमुख छह फोकस क्षेत्रों में आनुवंशिक त्वचा रोग, सूजन संबंधी रोग, इम्यूनोडर्मेटोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और त्वचा इमेजिंग, त्वचा कैंसर और बायोबैंकिंग शामिल हैं।

यह पहल मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी - इससे दुर्लभ बीमारियों का शीघ्र निदान, एक्ज़िमा व सोरायसिस जैसे रोगों के लिए अनुकूलित उपचार योजनाएं, त्वचा कैंसर के आरंभिक संकेतों की एआई आधारित पहचान तथा आनुवंशिकी और पर्यावरण के प्रभावों की बेहतर समझ संभव हो सकेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 2 से 4 बजे तक बाल त्वचा रोग क्लिनिक भी संचालित की जा रही है, जो पुरानी त्वचा बीमारियों से पीड़ित बच्चों को उच्च स्तरीय देखभाल प्रदान करेगी। यह पहल न केवल रोगियों के लिए, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बीमारियों के व्यवहार की समझ से नीति-निर्माताओं को अधिक प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, एम्स भोपाल त्वचा जीवविज्ञान, एआई इन डर्मेटोलॉजी, और क्लीनिकल ट्रायल्स के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भावी चिकित्सक-विज्ञानियों की एक नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, यह पहल एम्स भोपाल की विज्ञान आधारित रोगी देखभाल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अनुसंधान और क्लीनिकल सेवाओं के समन्वय से हम दुर्लभ बीमारियों का शीघ्र निदान और सामान्य रोगों का वैयक्तिक उपचार सुनिश्चित कर पाएंगे। इस पहल की प्रमुख अनुसंधानकर्ता ने बताया कि हमने देखा है कि एक ही बीमारी अलग-अलग मरीजों में अलग तरह से व्यवहार करती है। ट्रांसलेशनल डर्मेटोलॉजी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ऐसा क्यों होता है और हम उपचार को उसी अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। इस अवसर पर डीन (अकादमिक) सहित त्वचा रोग, ट्रांसलेशनल मेडिसिन और जैव रसायन विभागों के संकाय सदस्य उपस्थित रहे।

वरुण कपूर बने डीजी जेल

गृह विभाग ने जारी किया आदेश, सोनाली मिश्रा के स्थान पर भी होगी नई पोस्टिंग

भोपाल। वरुण कपूर नए डीजी जेल बन गए हैं। इसका आदेश गुरुवार दोपहर गृह विभाग ने जारी किया है। कपूर के पहले जेल डीजी जीपी सिंह आज सेवा निवृत्त हो गए हैं। उधर एडीजी चयन सोनाली मिश्रा को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना के लिए गृह विभाग ने रिलीव कर दिया है।

एम्स भोपाल के ईएनटी विभाग द्वारा विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान जनस्वास्थ्य जागरूकता और कैंसर की रोकथाम की दिशा में लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में, एम्स भोपाल के ईएनटी हेड और नेक सर्जरी विभाग द्वारा 28 जुलाई 2025 को विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस के अवसर पर एक विशेष जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संस्थान परिसर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विभाग के वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने की। कार्यक्रम में विभाग के चिकित्सकों, रेजिडेंट डॉक्टरों, मरीजों और आम नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को मुख एवं ग्रीवा कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों, स्वयं परीक्षण की विधियों, रोकथाम के उपायों और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों ने कैंसर की स्क्रीनिंग में सहयोग किया। तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों को समझाया तथा स्वयं परीक्षण की व्यावहारिक विधियों का प्रदर्शन किया। ईएनटी ओपीडी क्षेत्र में उपस्थित मरीजों को सूचनापरक पर्चे वितरित किए गए और उन्हें व्यक्तिगत परामर्श भी प्रदान किया गया। इस जन-जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आयोजित की गईं। ईएनटी ओपीडी क्षेत्र में मरीजों को मुख के कैंसर के लक्षणों, तंबाकू एवं गुटखा सेवन से होने वाले खतरे तथा नियमित जांच की आवश्यकता के बारे में बताया गया। आउटरीच सेवा केंद्र में विभाग द्वारा निःशुल्क मौखिक स्क्रीनिंग की गई और संदिग्ध मरीजों को आगे की जांच हेतु पंजीकृत किया गया। मरीजों को सरल भाषा में यह भी सिखाया गया कि घर पर आईने और रोशनी की सहायता से स्वयं मुख की जांच कैसे करें। तंबाकू और सुपारी सेवन से संबंधित खतरों पर आधारित पंपलेट वितरित किए गए और तंबाकू छोड़ने के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए गए। इसके साथ ही मरीजों को एम्स भोपाल में उपलब्ध मुख एवं ग्रीवा कैंसर के लिए आधुनिक सर्जिकल, रेडिएशन और कीमोथेरेपी सेवाओं की जानकारी भी दी गई।

इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, एम्स भोपाल आमजन को प्रभावित करने वाले कैंसर की समय पर पहचान और समुचित इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस हमें इस रोग की रोकथाम और समय पर उपचार की महत्ता का स्मरण कराता है। इस प्रकार के आयोजन नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और उन्हें कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

हर घर में एक पेड़ का संकल्प लेकर ग्राम खुर्दा में निकाली हरियाली यात्रा

बैतूल (निप्र)। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था ग्राम खुर्दा द्वारा नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन बड़े उत्साह और जनभागीदारी के साथ किया गया। हर घर पौधा, घर-घर पौधा के संकल्प को लेकर नाग पंचमी के अवसर पर ग्राम में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने पौधों के साथ भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच श्री सेवाराम धुर्वे, ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपेलाल उईके एवं श्री शिवचरण उईके उपस्थित रहे। नवांकुर संस्था के सदस्य श्री लवकेश मोरसे ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि संस्था का प्रयास है कि ग्राम खुर्दा का हर घर एक पेड़ से युक्त हो और अगले 5 वर्षों में ग्राम खुर्दा ग्रीन गांव के रूप में जाना जाए। इस अभियान के तहत प्रत्येक महिला को कम से कम 11 पौधों की वर्षभर देखरेख करने की प्रेरणा दी गई है। अगले वर्ष तक लगभग 5500 पौधे रोपण योग्य होकर तैयार होंगे , जो 500 नवांकुर सखियों की देखरेख में पनपेंगे। जिसे वे अपने परिवार के किसी विशेष आयोजन जैसे जन्मदिन या पुण्यतिथि पर रोपेंगी। कलश यात्रा के दौरान दो दिन से लगातार बारिश में भी महिलाओं के हाथों में पौधे और जुबान पर हर घर पौधा -घर घर पौधा, पर्यावरण बचाओ जैसे नारे थे, जिससे पूरे ग्राम में पर्यावरण चेतना की गूंज सुनाई दी। इस उत्सव में पुरुष वर्ग एवं युवा भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सचिव दीपेलाल उईके, शिवप्रसाद कवड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती शर्मिला बाई, आशा कार्यकर्ता एवं समस्त ग्रामवासी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से जलमग्नीय पुल-पुलियों पर बंद किया गया आवागमन

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जलमग्नीय पुल-पुलियों तथा रपटों पर पानी होने की स्थिति में बैरिकेड्स लगाकर इन मार्गों को बंद कर दिया गया है तथा यहां कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और पुल-पुलियों पर पानी होने की स्थिति में नागरिकों को इन्हें पार करने से रोक रहे हैं, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पुल-पुलियों पर बाढ़ का पानी होने की स्थिती में बेरिकैड्स लगाए जाएं और नागरिकों को इन्हें पार करने से रोका जाए तथा सुरक्षित मार्गों से आवागमन संचालित कराया जाए, ताकि दुर्घटनाएं न हों। 3 लेक्टर श्री बालागुरु के. ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि लगातार हो रही वर्षा के कारण जिन पुल, पुलिया, रपटों के ऊपर पर पानी बह रहा हो, उन्हें पार नहीं करें। उन्होंने नागरिकों से यह भी अपील की है कि बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर जाये तथा उन मार्गों से नहीं जाएं जिनपर नदी-नालों पर बने पुलों के ऊपर पानी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है।

आईगोट कर्मयोगी पोर्टल प्रशासनिक क्षमता संवर्धन और कौशल विकास के लिए उपयोगी: श्री जैन

आईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न

बैतूल (निप्र)। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए आईगोट कर्मयोगी पोर्टल पर जिला अधिकारियों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने सभी अधिकारियों को इस पोर्टल की उपयोगिता, विशेषताओं एवं कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जैन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी के तहत विकसित यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। इस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के ई-लर्निंग कोर्स उपलब्ध है जो कर्मचारियों को समय, स्थान और विषय के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आईगोट कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य प्रशासनिक गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसके माध्यम से कर्मचारी नई तकनीकों, सरकारी नीतियों और कार्यप्रणालियों से स्वयं को अद्यतन रख सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान ई गवर्नेंस प्रबंधक श्री विवेक सूर्यवंशी द्वारा आईगोट पोर्टल के रजिस्ट्रेशन , लॉगिन, कोर्स चयन, मूल्यांकन एवं प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का डेमो दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल का उपयोग करने, नए कोर्स करने और अपने ज्ञान को अद्यतन रखने के संबंध में जानकारी दी।

मूंग उपार्जन की अधिकारियों द्वारा की जा रही सतत मॉनिटरिंग

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले में किसानों से मूंग खरीदी का कार्य नियमित रूप से सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार एवं उपार्जन समिति के अधिकारी निरंतर उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उपार्जन केंद्रों पर तुलाई व्यवस्था, गुणवत्ता मापदंड, परिवहन, भुगतान सहित किसानों की समस्या की सतत निगरानी कर उनका निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में नायब तहसीलदार पिपरिया श्री नीरज सिंह बैस द्वारा पिपरिया स्थित इंद्रेश वेयर हाउस के उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया गया एवं उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। इसी प्रकार बनखेड़ी तहसील में भी नायब तहसीलदार सुश्री अंजू लोधी द्वारा समनापुर उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ

सीहोर (निप्र)। एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में अनेक नशामुक्ति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अभियान के तहत सीहोर स्थित चर्च ग्राउंड पर नशामुक्ति शपथ ग्रहण एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला, एएसपी श्रीमती सुनीता रावत और जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती रूबिका देवान सहित खिलाड़ियों द्वारा नशामुक्ति एवं जिले को नशामुक्त बनाने की शपथ ली गई और पौधरोपण किया गया।

उद्योगों में हड़ताल की डेढ़ महीने पहले देनी होगी सूचना

श्रम विधेयक पारित, विपक्ष ने किया वॉकआउट, कहा- ये मजदूरों का शोषण बढ़ाएगा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अब उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी करने के लिए उद्योग प्रबंधन को डेढ़ महीने पहले सूचना देना होगी। गुरुवार को विधानसभा ने इससे संबंधित श्रम विभाग के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है।

कांग्रेस विधायकों ने इसे मजदूरों का शोषण बढ़ाने वाला बताया और इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस विधेयक से मजदूरों का हड़ताल और आंदोलन करने का अधिकार छीन जाएगा। यह ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाला है।

गुरुवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई हुई है, और सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है।

श्री सिंघार ने आरोप लगाया कि जहां मीडिया की पहुंच नहीं होती, ऐसे दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और वहां त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती। सरकार अपराधों का वर्गीकरण कर आंकड़ों को छिपाने का प्रयास कर रही है, जबकि ज़मीनी सच्चाई यह है कि प्रदेश में 21,000 से अधिक बेटियां और महिलाएं लापता हैं। इसके बाद सरकार की ओर से कानून व्यवस्था पर दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में विरोध किया और बाद में वॉकआउट कर दिया। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश में बढ़ते एमडी ड्रग्स कारोबार, उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की संलिप्तता और सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा उन्हें दिए जा रहे संरक्षण के खिलाफ जोरदार और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि भाजपा पूंजीवादियों की सरकार है और पूंजीवादियों के लिए काम करती है। इधर, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के हित में है।

ठेकेदारों को कर्मचारी रखने की लाइसेंस प्रक्रिया में राहत- विधेयक में ठेकेदारों के लिए कर्मचारियों को रखने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में भी राहत दी गई है। साथ ही कारखानों के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस के लिए भी नियमों में संशोधन कर राहत देने का फैसला किया है। अलग-अलग संशोधनों को मंजूरी दिलाने के बाद सरकार ने कहा है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर बनेंगे। इस विधेयक के माध्यम से ठेकेदारों को लाइसेंस लेने के लिए 50 कर्मचारियों की लिमिट तय कर दी गई है, जबकि पहले यह 20 कर्मचारियों को लेकर थी।

ड्रग्स तस्करी और जव जिहाद मामले पर भी हंगामा

भोपाल में ड्रग्स तस्करी और लव जिहाद के मामले पर भी कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ नारेबाजी कर कहा- यह मछली किसकी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक नशे की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंचे।

कांग्रेस का सदन से वॉकआउट, जमकर नारेबाजी की

विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने इस विधेयक की प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव देते हुए कहा कि श्रमिकों का अधिकार है हड़ताल करना, आंदोलन करना और इस नियम के लागू होने के बाद श्रमिकों के अधिकार छीन जाएंगे। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।

इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मंत्री ने कहा है इसमें उद्योग के मालिक के बीच जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन सोहनलाल वाल्मीकि ने संशोधन प्रस्ताव वापस लेने से मना कर दिया।

यह विधेक मजदूरों के हित में : श्रम मंत्री पटेल

- श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- 2019 में जो श्रम कानून बने हैं, संशोधित हुए हैं उसका अनुमोदन इस विधेयक के माध्यम से किया जाना है।
- अगर किसी उद्योग को बंद करना है तो एक महीने पहले समय पर सूचना देनी होगी। उसके बाद ही उद्योग बंद करने की कार्रवाई हो सकेगी।
- जिन्हें उद्योग के खिलाफ आंदोलन करना है उन्हें पहले सूचना देनी होगी।
- पीएफ का पैसा उनके खाते में ही जाएगा, उससे कोई खा नहीं पाएगा। यह मजदूर के हित में लाया गया विधेयक है।

मजदूर का बुरा नहीं होने देंगे

विधानसभा में चर्चा के बाद श्रम विधेयक पारित घोषित कर दिया गया। इस पर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम मजदूर का सम्मान करते हैं लेकिन निर्माण की गति को बनाकर रखना होगा। मंत्री ने कहा- मैं आलोचना सुनने वाला हूं। विधेयक का विरोध करने वाले विधायकों से उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पर्ची पकड़ा दी गलत तो आप गलत ही पढ़ोगे ना।

श्रम विभाग का विधेयक शोषण बढ़ाएगा : कांग्रेस

विधानसभा में श्रम विभाग के विधेयक पर चर्चा में कांग्रेस विधायकों ने इसे शोषण बढ़ाने वाला बताया। पढ़िए, विपक्षी विधायकों ने क्या कहा- कांग्रेस विधायक विजय रेव नाथ चौरे - ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाला यह विधेयक श्रमिकों का और अधिक शोषण कराएगा। जिसे ठेका मिलता है, वह सरकार से एक कर्मचारी के लिए 15 हजार रुपए लेता है और श्रमिक को 5 हजार रुपए देता है।

कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस - आउटसोर्स कर्मचारी का ठेका सिस्टम से भारी शोषण होता है। बीच में बिचौलिए पैसे खा जाते हैं। इसलिए सीधे आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था होनी चाहिए।

कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम - सरकार को ठेकेदारों की चिंता है। श्रमिकों की चिंता नहीं है। इस विधेयक से यह बात साबित होती है कि भाजपा पूंजीवादियों की सरकार है और पूंजीवादियों के लिए काम करती है।

सीधे आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में पैसे डाले जाएं

कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस ने भी कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी का ठेका सिस्टम के माध्यम से भारी शोषण होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को सरकार 18 हजार का भुगतान करती है, लेकिन उन्हें 12 हजार रुपए से 13 हजार रुपए मिलते हैं। बीच में बिचौलिए पैसे खा जाते हैं, इसलिए सीधे आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था होनी चाहिए।

बरसात के दिनों में अतिक्रमण कर बनाया गया कोई भी मकान नहीं गिराया जाएगा : विजयवर्गीय

सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्न काल के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक विपिन जैन के एक सवाल के जवाब में कहा कि बरसात के दिनों में अतिक्रमण कर बनाया गया कोई भी मकान नहीं गिराया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस दौरान खाली जमीनों के इस्तेमाल का मामला उठाया। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल में भेल की जमीन पर इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जबलपुर से भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के सवाल के जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश में 50 हजार करोड़ रुपए खर्च कर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की तैयारी है। इसमें 25000 करोड़ राज्य सरकार और 25000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी।

रायसेन में बेतवा नदी की बाढ़ का मंजर

श्योपुर में बाढ़ में बहे चाचा-भतीजे के शव एक-दूसरे से लिपटे हुए मिले

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में अति भारी बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। श्योपुर में पार्वती नदी की बाढ़ में बहे चाचा-भतीजे के शव खेत में एक-दूसरे से लिपटे हुए मिले हैं। रायसेन में बेतवा ने विशाल रूप ले लिया है। आसपास के खेत, मंदिर और पुल डूब गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। शिवपुरी सिटी कॉलोनी में पानी भरने से हुए नुकसान के बाद नागरिकों ने आज चक्काजाम कर दिया। उन्होंने एबी रोड पर चक्काजाम किया। उनसे मिलने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता भी मौके पर पहुंच गईं। नागरिकों का दुख और गुस्सा देखकर उनके आंसू छलक पड़े। एसडीएम शिवानी पांडे उन्हें चुप कराती नजर आईं।

में माधव टाइगर रिजर्व की सांख्य सागर झील ओवरफ्लो हो गई है।

बुधवार को गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। कई रास्ते बंद रहे तो नर्मदा समेत अन्य नदियां उफान पर रही। इससे रास्ते भी बंद हो गए। 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टी रहेगी।

बुधवार को भारी बारिश का दौर थमा रहा। इससे पहले जबलपुर में ही सबसे ज्यादा 1 इंच पानी गिरा। वहीं, भोपाल, बैतूल, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, पचमढ़ी, रायसेन, श्योपुर, उज्जैन, दमोह, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, सागर, सिवनी, उमरिया, बालाघाट, शिवपुरी समेत 25 से अधिक जिलों में हल्की बारिश का दौर रहा।

गुना में बाढ़ पीड़ितों को देख नपा अध्यक्ष रो पड़ीं- गुना की न्यू

इंदिरा सागर बांध के 12 गेटों से छोड़ा जा रहा पानी- खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। इनमें 8 गेट 4 मीटर और 4 गेट साढ़े तीन मीटर तक खोले गए हैं। पावर स्टेशन पर पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन किया जा रहा है। करीब 12 हजार क्यूमेक्स से ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते नर्मदा में बाढ़ के हालात हैं।

सागर के नाले में बही गर्भवती का शव मिला- सागर में देवरी के रामघाट नाले पर बने पुल से बही गर्भवती महिला का शव 48 घंटे बाद गुरुवार को मिल गया है। शव पुल से करीब 5 किमी दूर पचासिया गांव के पास झाड़ियों में फंसा था। जिसे जबलपुर से आई एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संसद भवन में सौजन्य भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

राजगढ़ में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर 4 घंटे जाम

गायों की मौत के बाद गोसेवकों का प्रदर्शन ; हजार से ज्यादा वाहन फंसे रहे

सारंगपुर (नप्र)। राजगढ़ में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों ने गायों को कुचल दिया। 4 गायों की मौत के बाद गोसेवकों ने हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट किया। 4 घंटे से हजार से ज्यादा वाहन फंसे रहे।

विहिप, बजरंग दल और अन्य गोसेवक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पूर्व में जिला प्रशासन ने सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हुआ। जिनकी निजी गायें हैं, उन्हें चिन्हित कर अपने घरों में बांधने के निर्देश देना चाहिए। इसके अलावा

शहर में एक बड़ी गोशाला की स्थापना कर आवारा मवेशियों को वहां सुरक्षित रखा जाए।

एसडीएम रोहित बम्हौरे, एसडीओपी अरविंद सिंह, नपाध्यक्ष विकास करोड़िया और तहसीलदार आनंद जायसवाल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने गोसेवकों को आश्वासन दिया कि सड़कों पर बैठने वाली गायों को हटाने के लिए अलग से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। नगरपालिका पचोर की ओर से गोशाला के लिए जमीन आवंटित की जाएगी।

इसके बाद धरना खत्म हुआ और गोसेवक प्रशासनिक अमले के साथ स्थाई गोशाला के लिए जमीन देखने के लिए रवाना हुए।

डीजी जेल रिटायर, गुप्ता प्रमोट, बने रेल डीजी

गृह विभाग का जारी आदेश, सोनाली मिश्रा के स्थान पर अबसार की पोस्टिंग

भोपाल (नप्र)। जेल डीजी जीपी सिंह गुरूवार को सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर गृह विभाग ने 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी

वरूण कपूर को डीजी जेल बनाने का आदेश जारी किया। श्री कपूर स्पेशल डीजी आरएपीटीसी इंदौर में पदस्थ थे। उधर एडीजी चयन सोनाली मिश्रा को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना के लिए गृह विभाग ने रिलीव कर दिया है। इसके चलते एडीजी चयन के पद 1996 बैच के आईपीएस मो शाहिद अबसार को पदस्थ किया गया है। श्री अबसार वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में तैनात थे। श्री अबसार को अतिरिक्त डीजी पीटीआरआई और मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं गृह विभाग 2010 बैच के आईपीएस मो यूसुफ कुरेशी की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने हुए उप पुलिस महानिरीक्षक सायबर सेल से उप पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ तबादला किया हैं

दरअसल जेल डीजी जीपी सिंह के रिटायर होने के बाद सीनियर अफसरों में एडीजी रेल रवि कुमार गुप्ता को जेल डीजी बनाए जाने की चर्चा थी लेकिन देर शाम जारी आदेश में श्री गुप्ता को प्रमोट कर स्पेशल डीजी रेल बनाया गया। सूत्र बताते हैं कि जीपी सिंह के रिटायरमेंट का फायदा 1993 बैच की आईपीएस सोनाली मिश्रा को मिलना था लेकिन एडीजी चयन की जिम्मेदारी निभा रहीं सोनाली मिश्रा रेलवे मुख्यालय रेल सुरक्षा बल नई दिल्ली के महानिदेशक के पद पर जाइनिंग के लिए रिलीव हो गईं।

भोपाल के बड़ा तालाब में पानी लेवल बढ़ा

5 दिन में 4 फीट पानी आया, लेवल 1664.25 फीट पहुंचा, केरवा-कलियासोत में भी बढ़ा

भोपाल (नप्र)। भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब सिर्फ ढाई फीट खाली है। गुरुवार सुबह तक जलस्तर 1664.25 फीट पहुंच गया। 24 घंटे में 1 फीट और 5 दिन में 4 फीट पानी जमा हुआ। वहीं, कोलांस नदी 3 फीट ऊपर बही। केरवा और कलियासोत डैम में भी पानी का लेवल बढ़ा है।

सीहोर जिले में तेज बारिश होने पर ही कोलांस नदी उफान पर आती है। यह पानी सीधे बड़ा तालाब में पहुंचता है। बुधवार को नदी लेवल से 10 फीट ऊपर बही थी। इस कारण एक फीट पानी बढ़ गया। हालांकि, भोपाल और सीहोर में अब तेज बारिश का दौर थम गया है, लेकिन कोलांस लेवल से 3 फीट ऊपर बह रही है। इसलिए बड़ा तालाब में पानी बढ़ रहा है। बुधवार को कोलांस नदी में पानी का लेवल 10 फीट तक पहुंच गया था। शाम तक कम हुआ। वहीं, गुरुवार सुबह तक यह 3 फीट पर आ गया।

बुधवार को कोलांस नदी में पानी का लेवल 10 फीट भोपाल के इन डैमों में इतना पानी

कोलार डैम- इसका वॉटर लेवल 1516.40 फीट है। अभी इसमें 1497.83 फीट पानी जमा है। इस हिसाब से यह काफी खाली है। कोलार डैम से ही भोपाल शहर के 40 प्रतिशत हिस्से में पानी की सप्लाई की जाती है। पिछली बार जुलाई में इसके गेट खोलने पड़े थे।

केरवा डैम- कुल 1673 फीट वाले केरवा डैम में अब तक 1663.18 फीट पानी आ चुका है। तेज बारिश होने के बाद डैम में पानी का लेवल बढ़ जाएगा।

कलियासोत डैम- डैम का अभी वॉटर लेवल 1649.93 फीट है। इसकी कुल जलभराव क्षमता 1659.02 फीट है। इसके चलते डैम अभी भी करीब 9 फीट खाली है। बड़ा तालाब के गेट खुलने पर कलियासोत डैम में पानी आएगा और गेट खुल जाएंगे।

3 लाख आबादी की प्यास बुझाता है बड़ा तालाब

बड़ा तालाब को शहर की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसकी वजह यह वॉटर लेवल तो बेहतर रखता ही है। साथ में बड़ी आबादी की प्यास भी बुझाता है। बड़ा तालाब से हर दिन पुराने शहर समेत बैरागढ़ (संत हिरदाराम नगर) समेत आसपास के इलाकों की 3 लाख से ज्यादा आबादी को पानी की सप्लाई की जाती है।

20 प्रतिशत से ज्यादा इलाकों में पानी पहुंचता है। बड़ा तालाब से हर रोज 25 (मिलियन गेलन पानी प्रतिदिन) सप्लाई होता है। इसकी कुल जलभराव क्षमता 1666.80 फीट है।

बीएमओ ने गांव में एम्बुलेंस भेजने से मना किया

कहा- सड़क नहीं है, पुलिस कीचड़ में चलकर गांव पहुंची, ग्रामीण चारपाई पर ले गए शव

सतना (नप्र)। सतना के उसरहाई टोला गांव में 15 साल के लड़के की कुएं में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। गांव में सड़क नहीं होने के कारण पुलिस 800 मीटर तक कीचड़ भरे रास्ते से पैदल चलकर का पैर फंस गया और शव पानी के ऊपर आ गया।

ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। पुलिस कीचड़ में जैसे-तैसे पहुंची और पंचनामा बनाया। शव को पोस्टमार्ट्म के लिए ले जाना जरूरी था। एम्बुलेंस के आने से

घटनास्थल पर पहुंची। एम्बुलेंस ने तो आने से ही मना कर दिया।

घटना ग्राम पंचायत पुरवा स्थित उसरहाई टोला गांव की है। 15 साल का आशिकी कोल बुधवार दोपहर से लापता था। परिजन खेत से घर लौटे तो वह नहीं मिला। तलाश करने पर आशिकी का मोबाइल कुएं के पास पड़ा मिला। ग्रामीणों ने कुएं में काटा डालकर घुमाया, जिसमें आशिकी मना करने पर ग्रामीणों ने शव को चारपाई पर रखा और कंधे पर रखकर निकल पड़े।

बीएमओ बोले- सड़क नहीं है, हम नहीं आ सकते- ये घटना नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की विधानसभा रैगांव के अंतर्गत आने वाले गांव की है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां सड़क नहीं है।